



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३७] नई दिल्ली, साप्तमवार, सितम्बर १०, १९८८ (भाद्रपद १९, १९१०) -
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1988 (BHADRA 19, 1910)

(इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

विवरण-सूची	
भाग I—वर्ष 1—रक्षा मंदालय को छोड़कर भारत सरकार के मंदालयों और उच्चतम भ्यायालय हारा जारी की गई विधितर नियमों, विधियों तथा प्रावेशों और संबंधित प्रधिसूचनाएं	643
भाग I—वर्ष 2—(रक्षा मंदालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंदालयों और उच्चतम भ्यायालय हारा जारी की गई भरकारी प्रधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों प्रावि के सम्बन्ध में प्रधिसूचनाएं	1193
भाग I—वर्ष 3—रक्षा मंदालय हारा जारी किए गए वालों और प्रसंविधिक प्रावेशों के सम्बन्ध में प्रधिसूचनाएं	
भाग I—वर्ष 4—रक्षा मंदालय हारा जारी की गई भरकारी प्रधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, प्रावि के सम्बन्ध में प्रधिसूचनाएं	
भाग II—वर्ष 1—प्रधिनियम, प्राविधिक और विधियम	1325
भाग II—वर्ष 1—क—प्रधिनियमों, प्राविधिक और विधियों का हिस्टी प्रावि में प्रधिकृत पाठ	
भाग II—वर्ष 2—विधेयक तथा विधेयकी पर प्रवर समितियों के विल तथा रिपोर्ट	
भाग II—वर्ष 3—उप-वर्ष (i) भारत सरकार के मंदालयों (रक्षा मंदालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (सच सावित लोकों के प्रमाणनों को छोड़कर) हारा जारी किए गए सामान्य लोकितिक नियम (जिनमें सामान्य इकाय के वाले और उपविधियाँ प्रावि थीं सामिल हैं)	
भाग II—वर्ष 3—उप-वर्ष (ii)—भारत सरकार के मंदालयों (रक्षा मंदालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (सच सावित लोकों के प्रमाणनों को छोड़कर) हारा जारी किए गए सामान्य लोकितिक नियमों हारा जारी की गई प्रधिसूचनाएं	
भाग II—वर्ष 3—उप-वर्ष (iii)—भारत सरकार के मंदालयों (जिनमें रक्षा मंदालय भी सामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकारणों (सच सावित लोकों के प्रमाणनों को छोड़कर) हारा जारी किए गए सामान्य सांखिक नियमों और सांखिक प्रावेशों (जिनमें सामान्य स्वकान की उपविधियाँ भी सामिल हैं) को हिस्टी में प्रधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राज्यों के अध्य 3 या अध्य 4 में प्रकाशित होते हैं)	893
भाग II—वर्ष 4—रक्षा मंदालय हारा जारी किए गए संविधिक नियम और प्रावेश	
भाग III—वर्ष 1—उच्च भ्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा दरीक, संघ सोक लेका प्राविधि, रेल विधान और भारत सरकार से संबद्ध और प्रदीनस्थ कार्यालयों हारा जारी की गई प्रधिसूचनाएं	
भाग III—वर्ष 2—पेटेन्ट कार्यालय हारा जारी की गई पेटेन्टों प्रोट विजाइनों से संबंधित प्रधिसूचनाएं और लोकिति	883
भाग III—वर्ष 3—मुख्य भारुवरों के प्राधिकार के बाही प्रबन्धक तथा हारा जारी की गई प्रधिसूचनाएं	—
भाग III—वर्ष 4—विविध प्रधिसूचनाएं जिनमें सांखिक विधायों हारा जारी की गई प्रधिसूचनाएं, प्रावेश, विवाहन और लोकिति सामिल हैं	2059
भाग IV—वैद-भरकारी व्यवितयों और वैद-सरकारी विकायों हारा जारी किए गए विवाहन और लोकिति	183
भाग V—वैदेजा और विवाही दशों के भाग प्रोट मुख्य के बाबतों का विवाहन विवाह इनपुरक	

CONTENTS

PAGE	PAGE		
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	643	PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	893
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1103	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	883
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1325	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	—
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	2059
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	153
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	—	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	—
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	—	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	—
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	—		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नं० विल्सन-110001, दिनांक जून, 1988

संकल्प

सं० एम०-13043/12(7)/87-कृषि—यो के० कृषिपति, कुलपति, उक्तीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भूमीनेश्वर, दे० ढा० एन० पटनायक द्वारा कृषिपति का कार्यभार छोड़ने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम०-13043/12/87-कृषि के तहत छोड़ सं० 7 पूर्वी पठार तथा पर्वतीय छोड़ के लिए गठित आयोजन वल के प्रभावी रूप से श्री पटनायक अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनाएं भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12(10), 87-कृषि—डा० पू. पाटिल, कृषिविज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलोर से डा० नम् कृष्ण द्वारा कृषिपति का कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 3 जून, 1988 के संकल्प संख्या एम०-13043/12/87-कृषि के तहत छोड़ संख्या 10: दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय छोड़ के लिए गठित आयोजन वल के प्रभावी रूप से डा० नम् कृष्ण अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनाएं भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

दिनांक, 3 जून 1988

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एप्री(I)—कृषि मंत्रालय के कार्यभालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुशाव दिया था कि कृषि और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों को लोक-सागर तर्फ दिया दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की गणिती की 20 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता से 20 जूलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह नियंत्रण किया गया कि देश के 15 कृषिक-ज्यासाकु छोड़ कृषि सम्बन्धी आयोजन वा आपार होने आसिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक ज्यासाकु छोड़ों के आपार पर कृषि भास्तव्यी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की ज्यासाकु भी एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेंगी और उनके लिए विकास-निर्बन्ध देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में अन्य वालों के साथ-साथ, प्रत्येक कुषिक अन्वय छोड़ के लिए केन्द्रीय योजना वलों के गठन का निर्णय लिया गया था। परिवर्ती हिमालय के छोड़ सम्बन्धी योजना वल का गठन इस प्रकार होगा :—

छोड़ संघर्ष 1 : परिवर्ती हिमालय छोड़

आयोजन दल के छोड़

1. डा० महसिम सिंह, कृषिपति, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पतलमुर-176062 (हिमाचल प्रदेश)	भास्तव्य
2. इस छोड़ में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषिपति (1) कृषिपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सदस्य पालमपुर-173230 (हिमाचल प्रदेश)	सदस्य
(2) कृषिपति, डा० लाई० एस० परभार बागवानी और बानकी विश्वविद्यालय सोलन-173230, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
(3) कृषिपति शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	नदस्य
3. इस छोड़ में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, भाग्यनगर-226001, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर-190001 (जम्मू और कश्मीर)	सदस्य
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001	नदस्य
4. इस छोड़ में सचिव, पश्चिमालन (1) सचिव, पश्चिमालन, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(2) सचिव, पश्चिमालन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-190001	सदस्य
5. इस छोड़ में मुख्य वन संरक्षक (1) मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226001	सदस्य
(2) मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश शिमला-171001	सदस्य
(3) मुख्य वन संरक्षक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर-190001	सदस्य
6. इस छोड़ में सचिव, सिक्काई, उत्तर प्रदेश (1) सचिव, सिक्काई, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226001	सदस्य
(2) सचिव, सिक्काई, हिमाचल प्रदेश शिमला-171001	सदस्य

(३) सचिव, सिंचाई, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर—१९०००१	सदस्य
७. इस क्षेत्र के भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
८. नावांव का प्रतिनिधि	
९. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण, ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि श्री मुमाल मंदापुरकर, सूल, पी० ओ० जगजीत नगर, सोलन—१७३२०३, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
१०. योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
११. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
१२. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
१३. जम संभालन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
१४. प्रो० ए० एस० पुरोहित, श्रीनगर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	सदस्य
१५. डा० आर० स्वरूप, उप निदेशक, कृषि विभाग अनुसंधान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिलाला, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य—सचिव
४. योजना दल के विचारणीय विषय में होंगे:—	
(१) मृदा, पूर्तल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और अन्य मन्दिर क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय सम्बाबनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और अंकड़े एकत्र तथा संकलित करना;	
(२) उपर्युक्त (१) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीय करण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;	
(३) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;	
(४) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपर्युक्त कृषि-प्रोसेसिंग त्रियालायों के बारे में सिफारिश करना;	
(५) मध्यमावधि (५ वर्ष) और दीर्घावधि (१० से १५ वर्ष) क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपर्युक्त स्टीम/कार्बनेट तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;	
(६) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाय में लेना और यह विवरण क्षेत्री तो अध्ययन करना;	
(७) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नोति मन्दिरी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;	
(८) अपने कार्य और उद्देश्यों में संगत अस्त पहलुओं पर विचार करना।	
५. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।	
६. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में भद्रस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला खाय, मरकारी मवस्यों के भास्त्रों में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य मरकारों/विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों, के भास्त्रों में योजना आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।	

७. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार समाहृकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य—सचिव हैं।

८. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ अक्टूबर, १९८९ तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य मरकारों के सभी सबधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

भक्ति

स० एम०-१३०४३/१२/८७—एर्डा(II)—कृषि मन्त्रालय के कायं-शालम की समीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने सुनाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-गमित नई विश्वा दिए जाने की आवश्यकता है। संवित्रों की समिति की २६ मई, १९८७ को दुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में २० जलाई, १९८७ को दुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार—विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के १५ कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

२. इन विवार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के मदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की विगराही करेगी और उनके लिए विश्वा-निर्णय देगी।

३. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बास्तों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र संस्था २ : पूर्वी हिमालय क्षेत्र

आयोजन दल के सदस्य

डा० पी० मी० बी० बीरा, कुलपति,

असम कृषि विश्वविद्यालय

पी० ओ० बारमेटा, जोरहाट—८८५०१३

असम।

२. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

कुलपति, विद्यान चन्द्र,

मदस्य

कृषि विश्वविद्यालय,

पी० ओ० मोहनपुर, हरिधाटा,

नादिया—७४१२५२, पश्चिम बंगाल

३. इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन आयुक्त और राज्य कृषि सचिव

(१) कृषि उत्पादन आयुक्त, असम, दिसपुर,

(२) सचिव (कृषि) पश्चिम बंगाल, कलकत्ता सदस्य

(३) विकास आयुक्त सचिव, कृषि अर्थात् विद्यालय, शिलाम

शिलाम

सदस्य

(४) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि मणिपुर,

इमफाल

सदस्य

(५) कृषि उत्पादन आयुक्त, मेघालय, शिलाम

(६) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि मिजोरम,

अयंगल

सदस्य

४. विकास आयुक्त/सचिव, कृषि मणिपुर,

(7) विकास आयुक्त/सचिव, कृषि नागार्लैड, कोहिमा	सदस्य
(8) आयुक्त तथा सचिव, कृषि, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) सचिव, कृषि, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य
4. इस थेट्रे में सचिव, पशुपालन	
(1) सचिव, पशुपालन, असम, दिसपुर	भवस्य
(2) सचिव, पशुपालन, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) सचिव, पशुपालन, अस्सणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) सचिव, पशुपालन, मेघालय, शिलाय	सदस्य
(5) सचिव, पशुपालन, मणिपुर, इम्फाल	सदस्य
(6) सचिव, पशुपालन, मिजोरम, अयलल	सदस्य
(7) सचिव, पशुपालन, नागार्लैड, कोहिमा	गदस्य
(8) सचिव, पशुपालन, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) सचिव, पशुपालन, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य
5. इस थेट्रे में मुख्य वन मंत्रालय	
(1) मुख्य वन संरक्षक, असम, गुवाहाटी	सदस्य
(2) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) मुख्य वन संरक्षक, अस्सणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) मुख्य वन संरक्षक, मणिपुर, इम्फाल	गदस्य
(5) मुख्य वन संरक्षक, मेघालय, शिलाय	सदस्य
(6) मुख्य वन संरक्षक, मिजोरम, अयलल	सदस्य
(7) मुख्य वन संरक्षक, नागार्लैड, कोहिमा	सदस्य
(8) मुख्य वन संरक्षक, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) मुख्य वन संरक्षक, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य
6. इस थेट्रे में सिचाई सचिव	
(1) सचिव, सिचाई, असम, दिसपुर	सदस्य
(2) सचिव, सिचाई, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	सदस्य
(3) सचिव, सिचाई, अस्सणाचल प्रदेश, ईटानगर	सदस्य
(4) सचिव, सिचाई, मणिपुर, इम्फाल	सदस्य
(5) सचिव, सिचाई, मेघालय, शिलाय	सदस्य
(6) सचिव, सिचाई, मिजोरम, अयलल	सदस्य
(7) सचिव, सिचाई, नागार्लैड, कोहिमा	सदस्य
(8) सचिव, सिचाई, त्रिपुरा, अगरतला	सदस्य
(9) सचिव, सिचाई, सिक्किम, गंगटोक	सदस्य
7. इस थेट्रे में नहकारी भूमि विकास ब्रैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
8. नागर्लैड का प्रतिनिधि	सदस्य
9. इस थेट्रे में फसल, फलरोपण/प्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० ओ० का, प्रतिनिधि	सदस्य
श्री नटवर ठक्कर, नागार्लैड गोद्वी आश्रम, पी० ओ० चूचूपिमसंग जिला मोकाकचंग, नागार्लैड	सदस्य
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
13. जन संमाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
14. श्री ओ० ज्ञपि, निदेशक पश्चिम नायडू शिमालय विडियोपर,	सदस्य
दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	
15. ए० पी० डी० सेक्युरिटी निदेशक, कृषि आयिक अनुसंधान केन्द्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, पी० सी० बारमेटा,	सदस्य-सचिव
जोरहाट-785013 (असम)	
4. योजना वल के विचारणीय विषय ये होंगे :—	
(1) मृदा, भूतल और सूरत जल, फसल, पश्चाति, पशुओं, भीषणहोने और अन्य सम्बद्ध लोकों, प्रौद्योगिकीय संसाक्षणाओं और इन श्रेष्ठों के व्यवन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलवानों के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकल तथा बंकलिन करना;	
(2) उपयुक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचनाओं की जांच करना और जाननामक आयोगत प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्लीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;	
(3) ज्ञान और उप-क्लीयों के लिए फसल-पश्चाति सेवार करना और उसकी नियायिकी करना;	
(4) फसल-मिश्र कृषि, बानिकी, पशुपालन और ज्ञान के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोमोशन विकासलायों के बारे में नियायिकी करना;	
(5) मध्यावधि (5 वर्ष) और दीधावधि (10 से 15 वर्ष म) जीव के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीम/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;	
(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य क्षेत्र में ज्ञान और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;	
(7) इन श्रेष्ठों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष स्पष्ट से विस्तीर्ण संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;	
(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पशुसूची पर विचार करना।	
5. योजना वल का अध्यक्ष, याव चाह तो प्रम्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।	
6. इस वल की बैठकों के व्यवन्ध में सदस्यों के यात्रा खत्ते/दिनिक भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विशेषज्ञों/ मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विधायिकालयों द्वारा बहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना वल के वीर-सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।	
7. योजना वल के सम्बन्ध में सारा पलायकार सलाहकार (हृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव है।	
8. योजना वल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-भावशक्ता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।	

प्रादेश

प्रादेश दिया जाता है कि आयोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों,
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह प्रादेश दिया जाता है कि संकल्प को सामन्य सूचनाएं भारत
के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं. एम. -13043/12/87-एप्री(III)।—हृषि मंसालय के काव्य-
मालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुनाय दिया था कि हृषि
और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-सारेह नहीं बिहा दिया जाने
की आवश्यकता है। मवियों की समिति की 26 मई, 1987
को हुई बैठक में योजना आयोग के उपायकर्ता की अध्यक्षता में
20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर
और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के
15 हृषिक-जलवायु क्षेत्र हृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने आहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, हृषिक जलवायु क्षेत्रों के
आधार पर हृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के
सदस्य (छाती) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया।
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परि-
योजना को विधिवत् गतिविधियों की निगरानी करेंगी और उनके लिए
विधा-निरेत्र देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक
हृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए लेखीय योजना बदलोंके गठन का निर्णय
किया गया था। निम्न गोण का मैदानी लेख सम्बन्धी योजना दस का गठन
इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र सं. 3 : निम्न गोण का मैदानी लेख
आयोजन दस के सदस्य

1. प्रोफेसर डी० के० यास गुप्ता, उपकुप्रति विधान चम्भ लृषि विश्वविद्यालय हरिहाटा (परिवहन बंगाल)	अध्यक्ष
सदस्य	
2. इस क्षेत्र में हृषि उत्पादन आयुक्त और हृषि सचिव हृषि उत्पादन आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	
3. इस क्षेत्र में पश्चिमान सचिव सचिव, पश्चिमान पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	
4. इस क्षेत्र में मुख्य बन संरक्षक मुख्य बन संरक्षक पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	
5. इस क्षेत्र में सचिव निचाई सचिव निचाई पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता	
6. क्षेत्र में महाकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	
7. नाबाई का प्रतिनिधि	
8. इस क्षेत्र में एन० जी० के कमल, कल रोपण/ग्रामीण विकास में गम्भीर विशेषज्ञ/प्रतिनिधि श्री वी० एम० प्रग्रामाल, अध्यक्ष, ग्रामीण विकास स्थाई समिति, भारत ईमानी संस्करण, भारत चैम्बर 23, हैमन्त दामू, सरकारी, कलकत्ता-1	
9. योजना आयोग का प्रतिनिधि	
10. भारतीय हृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि	
11. हृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि	
12. जल संवाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि	
13. प्रोफेसर ए० के० साहा, ब्रेजीडेसी कालेज, कलकत्ता। इस क्षेत्र में हृषि आर्थिक प्रमुखान केन्द्र के निःश्वास	

14. प्रो एस के वलता, निवेशक

हृषि मार्गिक अनुसंधान केन्द्र
विश्वभारती विश्वविद्यालय
शान्तिनिकेतन (न० बंगाल)-731235

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:—

- (1) मृदा, मूरल और भूगत अव, फपत, पद्धति, पशुओं, पीलकेन्द्रों
और अन्य गम्भीर भैंड भेत्ताओं, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन
क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक
पहलुओं के बारे में संगत सूक्ष्मा और आंकड़े एकत्र नदा
संकलित करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचनाओं की जांच करना
और पश्चासनतम् योजना प्रयोजनों के लिए यदि किसी
उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- (3) अन्न और उप-क्षेत्रों के लिए कमल-पद्धति तैयार करना
और उसकी सिफारिश करना;
- (4) कमल-पिच्छ दृष्टि, वार्षिको, पशुपालन और क्षेत्र के लिए
उपयुक्त हृषि-प्रोटोकॉल क्रियाकलानों के बारे में सिफारिशें
करना;
- (5) भृष्मगावधि (5 वर्ष) और दीर्घवधि (10 से 15 वर्ष) में
क्षेत्र के हृषिक-विकास के लिए उपयुक्त स्तरोंमें/कार्यक्रम तैयार
करना और उनकी सिफारिश करना;
- (6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना
और पर्यावरण की तोहनी अध्ययन करना;
- (7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी
उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की
जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;
- (8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत मन्य पहलुओं पर विचार
करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि जूहे तो मन्य विशेषज्ञों/एन० जी०
ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के योजना भर्ते/वैनिक
भर्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/
मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें
से सभी हैं और योजना दल के गैर-सरकारी मददस्यों, के मामले में योजना
आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा प्रवाचार सलाहकार (हृषि)
योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति
के सदस्य-सचिव है।

8. योजना दल अपनी प्रतिरिम रिपोर्ट, यथा-प्रावश्यकता प्रस्तुत
कर सकता है और अपनी प्रतिरिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत
करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि योजना दल के अध्यक्ष और सदस्यों
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के तभी संबंधित मंत्रालयों और
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजो जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनाएँ भारत
राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

—प्र-सचिव

संकल्प

नं० एम -13043/12/87-एग्री(IV) —हृषि मंत्रालय के कार्यालय की समीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने मुसाव दिया था कि हृषि और भारीण विकास के कार्यवर्ती को क्षेत्र-गणेश नई विधा दिए जाने की आवश्यकता है। समिति की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपचालक की समझदान में 20 जून ई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विधा पर आग्रह दिवार-विमर्श किया गया। यह निर्णय दिया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु बेंड हृषि सम्बन्धी आयोजन का आवाह होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आवाह पर हृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (हृषि) की समझदान में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। समंजित केन्द्रीय विधायिकों के निविव इस परिविति के सदस्य हैं, तो इस परियोजना की विषय विधायिकों की विधायिकों करेंगी और उनके निवार-निर्देश देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के आवास-साध्य प्रत्येक हृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना थलों के गठन का निर्णय लिया गया था। मध्य नंगा का घैदानी और सम्बन्धी योजना बल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० 4: मध्य नंगा का घैदानी क्षेत्र
आयोजन बल के सदस्य

1. डा० कीर्ति सिंह,	अध्यक्ष
कुलपति, नरेन्द्र देव हृषि और प्रौद्योगिकी विषयविद्यालय	
नरेन्द्र नगर,	
फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य हृषि विषयविद्यालयों के कुलपति, कुलपति, राजेन्द्र हृषि विषयविद्यालय, पूसा—समस्तीपुर— बिहार—848125	
---	--

3. इस क्षेत्र में हृषि उत्पादन आयुक्त और हृषि सचिव	
--	--

- (1) हृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
- (2) हृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार सरकार, पटना।

4. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव	
--------------------------------	--

- (1) सचिव, पशुपालन,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
- (2) सचिव, पशुपालन,
बिहार सरकार, पटना

5. इस क्षेत्र में मुख्य बन संरक्षक	
------------------------------------	--

- (1) मुख्य बन संरक्षक
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
- (2) मुख्य बन संरक्षक,
बिहार सरकार, पटना

6. इस क्षेत्र में मिकाई सचिव	
------------------------------	--

- (1) सचिव सिवाई
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
- (2) सचिव सिवाई
बिहार सरकार, पटना

7. इस क्षेत्र में भूकारी भूमि विकास बैंक मंड़ का प्रतिनिधि	
--	--

8. नाश्ताई का प्रतिनिधि	
-------------------------	--

9. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण, प्राभीण विकास से संबंधित एन० जी०

ओ० का विशेषज्ञ प्रतिनिधि

श्री प्रेम भाई, निवेशक,

हृषि उत्पादन संस्थान,

बनकारी सेवाशाम,

गोविन्दपुर, मिर्जापुर जिला

उत्तर प्रदेश।

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय हृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

12. हृषि और महाकारिना विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० के० एस० विष्वप्रामी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

15. प्रो० एस० के० दरला, निदेशक, सदस्य—सचिव

हृषि—आधिक केन्द्र, विष्वविद्यालय
ग्रामिस निकेतन (पश्चिम बंगाल) —731235

4. योजना बल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(1) मूदा, भूतल और भूगत जल, फाल, पड़सि, पशुओं, मीनों को और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय संशावनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आकड़े एकत्र तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आकड़ों और सूचना की जाव करना और प्रजालनामक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रिकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फमल-पद्धति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(4) फमल-भिन्न हृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपर्युक्त हृषि—प्रोसर्सिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश करना;

(5) सध्यवाचधि (5 वर्ष) और दीर्घवाचधि (10 से 15 वर्ष) में जल के हृषि—विकास के लिए उपर्युक्त स्कीमें कार्यक्रम तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष कप से वित्तीय संस्थाओं की मूलिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि आहे तो अन्य विषेषज्ञों, एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में सह-योजित कर सकता है।

6. इस बल की बैठकों के मामूल्य में सरदरों के गाड़ा भरते/इनिक भरते पर होने वाला व्यय, सरकारी रस्तरों के मामूले में इन रिपोर्टों, मंत्रालयों/राज्य गरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जाएगा, जिनसे वे मम्बद्ध हों और योजना बल के यैर-सरकारी सदस्यों के मामले योजना आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।

7. योजना दल के मामूल्य में गारा पत्ताचार गालात्रकार (हृषि), योजना आयोग में किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के मदस्य—सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा गवर्नर बँगलादेश के मधी संबंधित भांडालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एप्री(5) — कृषि भांडालय के कार्यकालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुशाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की क्षेत्र—प्रापेक्ष नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में घोड़ना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जूलाई, 1987 को हुई बैठक में घोड़ना आयोग द्वारा इस निष्पत्ति पर और आगे विचार—विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया था कि देश के 15 कृषिक असदायु क्षेत्र इसी सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार—विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक असदायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेंगी और उनके लिए विशा—निर्देश देंगे।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक असदायु क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। कल्परी गंगा का भैदानी क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० ५ ऊपरी गंगा का भैदानी क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. श्री एस० एस० अहमद
कुलपति
चन्द्र शेखर आजाद कृषि और ग्रामीणीकी विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश
2. अध्यक्ष

सदस्य

3. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों का गुणात्मक
 - (1) कुलपति, गोविन्द बल्लभ वंश कृषि और ग्रामीणीकी विश्वविद्यालय, वंश नगर, बैनीताल, उत्तर प्रदेश
 - (2) कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि और ग्रामीणीकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
4. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. इस क्षेत्र में पशुपालन सचिव
सचिव, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
6. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक
मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. इस क्षेत्र में राज्य सिवाई सचिव
सचिव, सिवाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
8. इस क्षेत्र में महाकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
9. इस क्षेत्र में एन० जी० जी० के फसल, कल रोपण
ग्रामीण विकास संबंधी प्रतिनिधि
श्री रमेश श्रीबास्तव, सर्वोदय आश्रम,
सिकन्दरपुर, जिला हरयोदय, उत्तर प्रदेश
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों का प्रतिनिधि
12. कृषि और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन भांडालय का प्रतिनिधि
14. प्रोफेसर जे० एा० भिर, पालिमिकी विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस।

15. श्रो० ए० ही० शवर्मा, मानक निदेशक

सदस्य—सचिव

कृषि—आर्थिक अनुसंधान बैंक

इताहासाद विज्ञानियालय,

इताहासाद-३२१००२।

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

- (1) भूदा, भू-ए शू-भूगां जार, फसल, पढ़ति, पशुओं, मीनक्षेत्रों और मन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रांशुगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, नामांकित और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना भौत श्राक्षेत्र एकत्र तथा संकलित करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में विभिन्न भौक्ताओं और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीय उपका की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- (3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पर्वति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
- (4) फसल-भिन्न कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपर्युक्त कृषि-प्रोमोशनिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश करना;
- (5) मध्यमविधि (५ वर्ष) और वीधीविधि (१० से १५ वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपर्युक्त स्कीमों/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;
- (6) मानने उद्देश्यों के लिए अधेक्षिण अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;
- (7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्ती संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;
- (8) मानने कार्य और उद्देश्यों से संगत मन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि बाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० जी० घो० को अतिरिक्त राष्ट्रस्व के रूप में गढ़—योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यावा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला अन्य सरकारी यदवस्थों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/झारा बहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में मारा पक्काचार मनाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाए, जो हस परियोजना को केन्द्रीय समिति के सदस्य—सचिव है।

8. योजना दल के आनन्दी अन्वरिम रिपोर्ट, यथा—प्राविष्टकाला प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्विम रिपोर्ट ३१ अक्टूबर, १९८९ तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार नया राज्य सरकारों के गभी संबंधित भवानयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

मंकाल्प

मं० नम०-13043/12/87-एप्रील(VI)---कृषि संवालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुशब्द दिया था कि कृषि और प्रार्थीण विकास के कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय नई विणा विधि जाने की आवश्यकता है। सचिवों की मणित की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अव्यक्ति से 20 जूलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विवार-विवरण किया गया। यह निर्णय किया गया था कि रेण के 15 कृषिक जनवायु अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विभागों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवाया धेनू के आधार पर कृषि सम्बन्धी प्रयोजन करने के लिए योजना प्रायोग के सदस्य (कृषि) की अध्यधारा में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। गंभीर विभागों के मध्य इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की नियंत्रणी करेंगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देंगी।

3. केंद्रीय समिति की पहचान थैक में, अन्य जातों के माथ-माय प्रत्येक गृहिण जगत्वायु धेन के लिए धेनीय योग्यता वर्णों के गठन का लिप्तिय लिया गया था। गगा पार क। मैदानी धेन अस्थधीय योग्यता दल का उत्तर हम प्रकार होगा :—

क्षेत्र में ६ : गंगा पार का मैदानी क्षेत्र
आयोजित दल के गदस्य

1. डा० हरस्वरूप मिह
कुलपति, हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय
दिसार- 2004

अध्यक्ष

महस्य

- इस क्षेत्र में अन्य कृषि विष्वविद्यालय के कुलंपति
 (1) कुलपति, पंजाब कृषि विष्वविद्यालय, नुधियाना
 (2) कुलपति, राजस्थान कृषि विष्वविद्यालय बीकानेर।
- इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि मन्त्रिव
 (1) विकास आयुक्त, पंजाब, चंडीगढ़
 (2) सचिव, कृषि, हरियाणा, चंडीगढ़
 (3) सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर
 (4) सचिव, कृषि, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
- इस क्षेत्र में पशुपालन गविन
 (1) सचिव, पशु पालन, पंजाब, चंडीगढ़
 (2) सचिव, पशुपालन, हरियाणा, चंडीगढ़
 (3) सचिव, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर
 (4) सचिव, पशुपालन, दिल्ली
- इस क्षेत्र में मुख्य बन संरक्षक
 (1) मुख्य बन संरक्षक, पंजाब, चंडीगढ़
 (2) मुख्य बन संरक्षक, हरियाणा चंडीगढ़
 (3) मुख्य बन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
 (4) मुख्य बन तथा अन्य जीवन संरक्षक, दिल्ली
- इस क्षेत्र में राज्य सिक्खाई सचिव
 (1) मन्त्रिव, सिक्खाई, पंजाब सरकार, चंडीगढ़
 (2) सचिव, सिक्खाई, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
 (3) सचिव, सिक्खाई, राजस्थान सरकार, जयपुर
 (4) सचिव, सिक्खाई और बाहु नियन्त्रण, दिल्ली
- इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि
 नावाई का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में पन् ० जी० श्रो० के काला॒/कल गोपण/ग्रामीण
विकास से मन्बधित प्रतिनिधि
श्री मुन्दर लाल गाव० पन्म० डल्हू० प्राग० सी०,
पोस्ट ग्रामीण खारी॑ - १२३१०१ रेयाई॑, तहमोत्र,
जिन्ना महान् गढ, हरियाणा।

- योजना आयोग का प्रतिनिधि
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
- कृषि एवं महाकारिता विभाग का प्रतिनिधि
- जल संग्रहित मंत्रालय का प्रतिनिधि
- प्रो॰ पूर्वो वार्ड० सीहन राम
वनस्पति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महाराष्ट्र-मराठिवाला
उप निदेशक, कृषि आयिक अनुसंधान केंद्र
विल्हेम विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

4. योजना द्वारा के विचारणीय विषय में होंगे :—

- (1) मृदा, भूतल और भगत जन, फ़गन, पद्मति, पण्डित्रों और अन्य सम्बद्ध थेवकों, प्रौद्योगिकीय संसाक्षणार्थों और उन थेवकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में मंगत सूचना और आंदाझे प्रक्रिया तथा मंकलित करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में विभिन्न आंकड़ों और गूचना की जांच करना और प्रवालनात्मक भाष्योन्तर प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-अंकीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- (3) थेव और उप-थेवों के लिए फ़गन-पद्मति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
- (4) फ़सल-मिश्र कृषि, बानिकी, पशुपालन और थेवों के लिए उपग्रहित लूपि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश करना;
- (5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीवाविधि (10 से 15 वर्ष) में थेव के कृषि-शिकाय के लिए उपर्युक्त स्कीमें/कार्यपाल तैयार करना और उनकी सिफारिश करना;
- (6) अपने उद्देश्यों के लिए प्रोत्तिष्ठित अध्ययन कार्य द्वारा मेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना,
- (7) हन थेवकों के विकास के लिए प्रोत्तिष्ठित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप में विनीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना,
- (8) अपने कार्य और उद्देश्यों से मंगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना इन का अध्यक्ष, प्रदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० श्रो० को प्रतिरिक्ष मुद्रण के रूप में मह-योजित कर सकता है।

6 इस दत की बैठकों के सम्बन्ध में सदस्यों के यात्रा भत्ते, ईनिक भत्ते पर होने यात्रा व्यवं, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों, मंत्रालयों एवं ग्रन्तकारों विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों या योजना दत के ई-प्रशासनी सदस्यों के मामले में योजना यापोग द्वारा बहन किया जाएगा।

7.-योजना दल के गम्भीर में मारा पत्राचार सलाहकार (कृपि) योजना आयोग में किया जाए, जो इन परियोजना की केंद्रीय समिति-मंडल-समिति है।

8. योजना द्वारा आपनी अन्तर्राम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर देता है और आपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 दिसंबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

प्रावेश

भादेश दिया जाता है कि आयोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों, पारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह भादेश दिया जाता है कि संकल्प को मामत्य गूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

- संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एयी (VII)—कृषि मंत्रालय के कार्यचालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने मुख्य दिया था कि हृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को खेत-साधन नई दिशा दिए जाने की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जून 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एवं केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेंगी और उनके लिए दिशा-निर्देश देंगे।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य वासियों के साथ-साथ, प्रत्येक कृषिक जलवायु के लिए केन्द्रीय योजना दस्तों के गठन का निर्णय लिया गया था। पूर्वी पटार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० ७ : पूर्वी पटार और पर्वतीय खेत्र
आयोजन दल के सदस्य

1. श्री के० राममूर्ति, कुलपति, उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर अध्यक्ष
2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति
 - (1) कुलपति, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहापुर-मारिया।
 - (2) कुलपति, विरसता कृषि विश्वविद्यालय, राजीवी
 - (3) कुलपति, इंविरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर मध्य प्रदेश
 - (4) कुलपति, पंजो राज कृषि विद्यालय—अकोला, महाराष्ट्र
3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त और कृषि सचिव
 - (1) कृषि उत्पादन आयुक्त, विहार—पटना
 - (2) कृषि सचिव, पश्चिम बंगाल—कलकत्ता
 - (3) आयुक्त तथा सचिव, कृषि, उड़ीसा, भुवनेश्वर
 - (4) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल
 - (5) सचिव, कृषि, महाराष्ट्र, बम्बई
4. इस क्षेत्र में सचिव, पश्चिम
 - (1) सचिव, पश्चिम, विहार—पटना
 - (2) सचिव, पश्चिम बंगाल—कलकत्ता
 - (3) सचिव, पश्चिम, उड़ीसा—भुवनेश्वर
 - (4) सचिव, पश्चिम, मध्य प्रदेश—भोपाल
 - (5) सचिव, पश्चिम, महाराष्ट्र, बम्बई

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक

- (1) विहार गुड्य वन संरक्षक विहार, पटना
- (2) मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम बंगाल
- (3) मुख्य वन संरक्षक, उड़ीसा, भुवनेश्वर
- (4) मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल
- (5) मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र, पुणे

6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव, मिचाई

- (1) सचिव, मिचाई, विहार मरकार, पटना
- (2) सचिव, सिचाई, पश्चिम बंगाल मरकार, कलकत्ता
- (3) सचिव, मिचाई, उड़ीसा मरकार, भुवनेश्वर
- (4) सचिव, मिचाई, मध्य प्रदेश मरकार, भोपाल
- (5) सचिव, मिचाई, महाराष्ट्र मरकार, बम्बई

7. इस क्षेत्र में महाकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

8. नाबांड का प्रतिनिधि

9. फसल/फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित खेत्र में प००० जी० ओ० का प्रतिनिधि
 - (1) रामझण मिशन, राजीवी का प्रतिनिधि
 - (2) अन्युत दाम, एस० इक्स०० आर० मी० पोर्ट काशीपुर, कोरापुट, उड़ीसा

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा महकारिया विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संग्रहान मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० आर० आर० के० कद्दी, प्रमुख, संसाधन इंजीनियरिंग अध्ययन केन्द्र, आई० आई० टी०, पोदार्व, बम्बई

15. शा० टी० बी० एस० राज, प्रभारी निदेशक, कृषि अधीकारीस्त्र अनुसंधान केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय, बालटीयर-530003

4. योजना दल के विचारणीय विषय में होंगे :—

- (1) मुदा, भूस्त और भूगत, जन, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनक और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं अंदर कृषि क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एवं तथा संक्षिप्त करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में बर्जित आंकड़े और सूचना की जांच कर और प्रचलनार्थीक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि उप-समीक्षकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- (3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार कर और उसकी सिफारिश करना;
- (4) फसल-सिफारिश कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के उपर्युक्त कृषि-प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिश करना;
- (5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीर्घावधि (10 में 15 वर्ष) में कृषि-विकास के लिए उपर्युक्त स्कीम/कार्यक्रम तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
- (6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हास्य में होने और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन कराना;

(7) इन खेतों के विकास के लिए अपेक्षित भीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना वल का अध्यक्ष, चंद्रि चाहुं तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० को अन्तिरिक्षन सवालस्य के रूप में सह-योगित कर सकता है।

6. इस वल की बैठकों के सम्बन्ध में मदस्यों के पान्ना भत्ते/दिनिक पर हीने आला अन्य, सरकारी मदस्यों के मामले में उन विभागों/ललबों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे सम्बद्ध हो और योजना वल के गैर-सरकारी सदस्यों के मामले में भूमिका आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना वल के सम्बन्ध में सारा पत्राचार गलाहकार (कृषि), जा आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति सवालस्य-सचिव है।

8. योजना वल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत करता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत गा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन वल के अध्यक्ष और सदस्यों, रत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और आगों को संकलन की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकलन को सामान्य सूचनार्थ भारत राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकलन

सं० एम०-१३०४३/१२/८७—एरी (VIII)—कृषि संवालय के कार्य-लन की समीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि र यामीन विकाय कार्यकर्त्तों वो धन-सामेक नई दिग्गज जाने की शम्पकता है। सवियों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में जना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जूलाई, 1987 को हुई क में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श या गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलशायु झेत्र व सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषि जलशायु झेत्रों के धार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के रूप (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। इस केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की नियरानी करेंगी और उनके लिए गा—नियंत्रण देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य वारों के माथ—माथ, एक हृषिक जलशायु के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय या गया था। मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र संबंधी योजना दल का गठन प्रकार होगा :—

क्षेत्र सं० १ : मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र
आयोजन दल के सदस्य

१. डा० ई० के० शर्मा अध्यक्ष

कुनैति, जबाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म० प्र०) ५८२००२

सदस्य

२. इस खेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कृषिपति

(१) कुनैति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि नाय
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर

(२) कुनैति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

३. इस खेत्र में गभीर राज्यों के गभीर कृषि उत्पादन आयुक्त

(१) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल

(२) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश—लखनऊ

(३) सचिव कृषि, राजस्थान—जयपुर

४. इस खेत्र में सचिव, पशुपालन

(१) सचिव, पशुपालन, मध्य प्रदेश—भोपाल

(२) सचिव, पशुपालन, उत्तर प्रदेश—लखनऊ

(३) सचिव, पशुपालन, राजस्थान—जयपुर

५. इस खेत्र में मुख्य वन संरक्षक

(१) मुख्य वन संरक्षक—म० प्र०—भोपाल

(२) मुख्य वन संरक्षक—उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(३) मुख्य वन संरक्षक—राजस्थान—जयपुर

६. इस खेत्र में राज्य सचिव, मिचाई

(१) सचिव, सिचाई—मध्य प्रदेश—भोपाल

(२) सचिव, सिचाई—उ प्र०—लखनऊ

(३) सचिव, सिचाई—राजस्थान, जयपुर

७. महाकारी, भूमि विकास बैंक कोडरेसन का प्रतिनिधि

८. नामांडे का प्रतिनिधि

९. इस खेत्र में फगल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी और० के प्रतिनिधि

(१) श्री भारतेन्दु प्रकाश विज्ञान शिक्षा केन्द्र, तराही मुम्हारी गांव पोस्ट—टेंडप्रारी जिला—बांदा, उत्तर प्रदेश

(२) डा० ई० ई० नर्सना,

५३, जवाहर नगर,

टेलीफोन बैन्ड के सभीप

जयपुर—३०२००४ (फोन-६४५८७—प्राकास)

१०. योजना आयोग का प्रतिनिधि

११. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि

१२. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

१३. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

१४. श्री एम शी० शुच, भूमि

राष्ट्रीय मानव पुनर्वास योग परिवरण केन्द्र भोपाल

१५. डा० एम० राय

सदस्य—मिचिव

डी०, कृषि संकाय

कृषि प्रशंसास्त्र अनुसंधान केन्द्र

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय

जबलपुर—४८२००४

४. योजना वल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

(१) मदा, भूतल धूर भूगत जल, फसल, पशुओं, मीनखेत्रों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिवरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आकड़े एकत्र तथा संक्लिप करना;

(२) उपर्युक्त (१) में वर्णित आकड़ों और सूचनाएँ की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी उप-क्षेत्रीयपरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(३) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए कमल-पद्धति तैयार करना और उसकी शिकारिश करना;

(4) कमल-भिज्जि कृषि, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि-प्रोग्रामिंग विकासकार्यों के बारे में मिफारिशें करना;

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और शीर्षविधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि-विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करना और उनकी विकाशित करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी उपायों, विशेष रूप में विशेष संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में मिफारिशें करना;

(8) आगे उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एम० जी० ओ० को प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में महोर्जित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में संस्थाओं के यात्रा भर्ते/ईनिक भर्ते पर होने वाली अव्य, गरकारी भर्तयों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/गजय गरकारों/विष्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जाएगा, जिनसे वे गम्भीर हों और योजना दल के गैर-सरकारी संस्थाओं के मामले में योजना आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पवाचार गलाहकार (कृषि) योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के सदस्य—मन्त्रिवाल है।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा—आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी प्रान्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आवेदन

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और संस्थाओं, भारत सरकार तथा गजय सरकारों के वर्षीय संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आवेदन दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०—13043/12/87-एमी(ix) ---कृषि मंत्रालय के कार्य-चालन की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि कृषि और आमोंग विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र-संपेक्ष नहीं विश्व विद्या विए जाने की आवश्यकता है, मिचिको की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जूनाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-क्रिमर्श किया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जनवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. उन विचार-विमर्शों के परिणमस्वरूप, कृषिक जनवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के मिचिक इस समिति के गवर्नर हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की नियंत्रणी करेंगी और उनके लिए विशा-निर्देश देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कृषिक जनवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का

निर्णय लिया गया था। परिचमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा : -

क्षेत्र सं० ९ परिचमी पठार पर्वतीय क्षेत्र आयोजन दल के मदस्य

1. ए० के० आर० पंचार०
फूलपति, मराठवाड़ा कृषि विष्वविद्यालय,
परभानी-431402
महाराष्ट्र

मदस्य

2. इस क्षेत्र में प्रथम कृषि विष्वविद्यालयों के कुलपति
(1) कुलपति, एम० पी० के० शहरी,

अहमदनगर, महाराष्ट्र

(2) कुलपति,

पंजाबगढ़ कृषि विद्यालय,
प्रकोला, महाराष्ट्र

(3) कुलपति, ऐ० एन० के० श्री शी०

जवालपुर, मध्य प्रदेश

(4) कुलपति,

राजस्थान कृषि विष्वविद्यालय,
बीकानेर

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव

(1) सचिव, कृषि
महाराष्ट्र, बम्बई

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल

(3) सचिव, कृषि

राजस्थान,
जयपुर

4. इस क्षेत्र में सचिव, पशुपालन

(1) सचिव, पशुपालन,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई

(2) सचिव, पशुपालन,
मध्य प्रदेश, सरकार
भोपाल

(3) सचिव, पशुपालन, राजस्थान सरकार,
जयपुर

5. इस क्षेत्र के मुख्य बन संरक्षक

(1) मुख्य बन संरक्षक,
महाराष्ट्र, पुणे

(2) मुख्य बन संरक्षक,
मध्य प्रदेश, भोपाल

(3) मुख्य बन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

6. इस क्षेत्र में राज्य सचिव, मिचाई

(1) सचिव, मिचाई,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई

(2) सचिव, रिचाई, मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल

(3) सचिव, मिचाई,
राजस्थान सरकार, जयपुर

7. इस क्षेत्र में महाराष्ट्रीय विकास बैंकों का प्रतिनिधि

8. नाशाई का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल, फल रोपण/ग्रामीण विकास में संबंधित एन० जी० और का प्रतिनिधि

(1) श्री एन० जी० मालके

ग्राम गोरख प्रतिष्ठान, पोस्ट बाकम नं 1202
67, हाडापगार ग्रोवोगिक एस्टेट,
पुणे-411013

(2) प्रो० श्री० एन० डेउकर,

"कलात्मकालीन",
820/2, शिवाजी नगर,
पुणे-411004

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल समाधान मंत्रालय का प्रतिनिधि

15. श्री ढी० श्री० नारायण,
निदेशक, सामाजिक वार्ताली,

15. डा० श्री० एम० चित्रे

मदस्य मन्त्रिय

कृषि व्यवस्था-ग्रामीण अनुसन्धान केन्द्र

गोप्यता राजतीर्थ तथा ग्रामीण ग्रामीण संस्थान

पुणे-411004

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे—

- (1) मूदा भूमें और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीठेंद्रों और अन्य सम्बद्ध घोड़ों, ग्रोवोगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रों के मम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और ग्रामीण एकत्र तथा संकलित करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचनाओं की जांच करना और प्रकालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- (3) घोड़ों और उप क्षेत्रों के लिये फसल-पद्धति तैयार करना और उमड़ी सिफारिश करना;
- (4) फसल-मिश्र कृषि, वानिकी, पशु पालन और क्षेत्र के लिये उपर्युक्त कृषि प्रोमोशन विकासार्थी के बारे में सिफारिश करना;

(5) मध्यसातनधि (5 वर्ष) और दोषधिधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपर्युक्त राज्यों/कार्यक्रम करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिये घरेलित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रों के विकास के लिये अपेक्षित नीति मम्बन्धी उपायों विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिश करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० और को प्रतिरिक्षित मदस्य के रूप में सहयोगिता कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के मम्बन्ध में सदस्यों के बाबा भर्ते/वैनिक भर्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा बहत किया जायेगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा बहत किया जायेगा।

7. योजना दल के मम्बन्ध में भारा पत्राचार मलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के मदस्य मन्त्रिवाल हैं।

8. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा आवश्यकता, प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिम अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

प्रादेश किया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्री संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प वी प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

संकल्प 13043/12/87-एसी (X):—कृषि मंत्रालय के कार्यकालन की समीक्षा करते हुए, प्रधान मंत्री ने सुनाव दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। मचिवालों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग के उपायकर्ता की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार विस्तर किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक जलवायु भेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिये।

2. इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि मम्बन्धी आयोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के मन्त्रिवाल समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिये विश्वास देंगे।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य वालों के साथ-साथ प्रयोक्त कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। विधिनी पठार तथा पर्वतीय घेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र में 10 दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
आयोजन दल के मदस्य

1. डा० एम० श्री० पाटिष्ठ	प्रध्यक्ष
कूलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,	
बंगलौर-560024।	

सदस्य

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति

(i) कुलपति
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
धारवाड।

(ii) कुलपति,
प्रान्तीय प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद।

(iii) कुलपति
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय
कोयम्बटूर।

3. इस क्षेत्र में मंत्री राज्यों के सभी कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त,
कर्नाटक, बंगलौर।

(ii) कृषि उत्पादन आयुक्त,
प्रान्तीय प्रदेश, हैदराबाद।

(iii) श्रावुकन तथा भवित्व, कृषि
तमिलनाडु, मद्रास।

4. इस क्षेत्र में पशुपालन भवित्व

- मधित्र, पशुपालन
कर्नाटक, सरकार, बंगलौर।
- मधित्र, पशुपालन,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।
- समित्र, पशुपालन
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास।

5. इस क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक

- मुख्य वन संरक्षक, कर्नाटक, बंगलौर।
- मुख्य वन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद।
- मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु
मद्रास।

6. इस क्षेत्र में राज्य भवित्व (भिचाई)

- भवित्व (भिचाई) कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
- भवित्व, (भिचाई) आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।
- साक्षर (भिचाई) तमिलनाडु, मद्रास।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

8. योजना का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में कफल फलशेषण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० औ० का प्रतिनिधि

- श्री नरेन्द्र बेदी, यॉड इण्डिया प्रोजेक्ट
पेन्कोट्स-515170
ग्रन्टस्पुर, जिला, आन्ध्र प्रदेश
- प्र० शार० राधाकृष्णन,
नियेंगक
आधिक तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र,
निजामिया आवजरवेटरी कैम्पस,
बैंगलोर, हैदराबाद-500016

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भागीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल संमाधन संकालय का प्रतिनिधि

14. प्र० माथव गाडगिल, भागीय विभाग संस्थान,
बंगलौर।

15. डा० सी० अरुपुराजा
उपनिदेशक सहस्य भवित्व
कृषि आधिक अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास विश्वविद्यालय,
चेन्नै, त्रिपुराम, मद्रास-600005।

4. योजना वल के विचारणीय विषय में होंगे:-

- मूदा, भूगत और भूगत जल, कफल, पद्धति, पशुओं, भीनदेहों
और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय संसाधनों और इन
क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आधिक
पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा
सम्पर्कित करना।
- उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना
और प्रचासनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उप-
क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;
- शेष और उप क्षेत्रों के लिये कफल पद्धति तैयार करना और
उसकी सिफारिश करना,
- कफल भवित्व कृषि विभाग, पशुपालन और क्षेत्र के लिये उप-
युक्त कृषि प्रौद्योगिकीय क्रियान्वयों के बारे में सिफारिशें करना;
- मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीवानिधि (10 से 15 वर्ष) में
अन्वेषक कृषि विकास के लिये उपर्युक्त स्थीमें/कार्यक्रम तैयार
करना और उनकी सिफारिश करना;
- अपने उद्देशों के लिये अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना
और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;
- इन क्षेत्रों के विकास के लिये अपेक्षित तीति सम्बन्धी उपायों,
विषेष रूप से विनाई संस्थाओं की भूमिका की जांच करना
और उनको बारे में सिफारिशें करना;
- अपने कार्य और उद्देशों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार
करना।

5. योजना वल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० औ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में नह्योंजित कर सकता है।

6. इस वल की बैठकों के सम्बन्ध में सबस्ट्रों के बातों भने/इनिक
भने पर होने वाला व्यवसरकारी मदस्यों के मामले में उन विभागों/
मंत्रालयों/शायद सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जायेगा, जिनमें
ये सम्बन्ध हों और योजना वल के गैर सरकारी सदस्यों, के मामले में
योजना आयोग द्वारा बहन किया जायेगा।

7. योजना इस के सम्बन्ध में सारा पन्नोचार मलाहकार (कृषि),
योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति
के वदस्य भवित्व है।

8. योजना इस अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा आवश्यकता प्रस्तुत
कर सकता है और प्रत्यनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत
करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन इस के अध्ययन और सदस्यों, भारत
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संवंधित संबंधीय और विभागों को
महत्व की एक प्रति भेंटी जाये।

प्र० आदेश दिया जाता है कि गोक्षन का सामान्य सूचनार्थ भारत
के राज्यों में प्रसारित कराया जाये।

संकल्प

ग० एम०-13043/12/87-ए०शी०—कृषि मंत्रालय के कार्यालय की
सभी कार्यालयों के लिये योजना आयोग के सदस्यों, भारत
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संवंधित संबंधीय और विभागों को
महत्व की एक प्रति भेंटी जाये।

2. इन विचार-विभागों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के
आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिये योजना आयोग के सदस्य
(कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया।
संवंधित केन्द्रीय विभागों के समिति इस समिति के मदस्य हैं, जो इस परि-
योजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेगी और उनके लिये
दिनांक देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य वार्ताओं के साथ-साथ, प्रत्येक
कृषिक इनवायु क्षेत्र के लिये विभिन्न योजना इसों के गठन का निर्णय लिया

गया था। पूर्व तटीय, मैदान तथा पर्यावरण के सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:-

धन्व II पूर्व तटीय मैदान तथा पर्यावरण क्षेत्र योजना दल के गदम्य

1. डा० अणा राव, अध्यक्ष

मुलपति,
आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500030।

2. इस क्षेत्र में अन्य कृषि विश्वविद्यालय के उप कृलपति

(1) उप कूलपति, उड़ीसा कृषि नथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भुवनेश्वर।

(2) कूलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्पट्टूर।

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि सचिव

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

(2) आयुक्त तथा कृषि सचिव, तमिलनाडु, मद्रास।

(3) कृषि आयुक्त तथा सचिव, उड़ीसा भुवनेश्वर।

(4) सचिव (कृषि), पाण्डिचेरी, पाण्डिचेरी।

4. इस क्षेत्र में सचिव (पशु पालन)।

(1) सचिव (पशु पालन) आन्ध्र प्रदेश मरकार, हैदराबाद।

(2) सचिव (पशु पालन) तमिलनाडु मरकार, मद्रास।

(3) सचिव (पशु पालन) उड़ीसा मरकार, भुवनेश्वर।

(4) सचिव (पशु पालन) पाण्डिचेरी, प्रशासन, पाण्डिचेरी।

5. इस क्षेत्र में मुख्य बन संरक्षक

(1) मुख्य बन संरक्षक, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

(2) मुख्य बन संरक्षक, तमिलनाडु, मद्रास।

(3) मुख्य बन संरक्षक, उड़ीसा, भुवनेश्वर।

(4) मुख्य बन संरक्षक/बन नथा बन्य औवन अधिकारी पाण्डिचेरी, प्रशासन, पाण्डिचेरी।

6. इस क्षेत्र में सचिव (मिचाई)

(1) मिचिव (मिचाई) आन्ध्र प्रदेश मरकार, हैदराबाद।

(2) मिचिव (मिचाई) तमिलनाडु सरकार, मद्रास।

(3) मिचिव (मिचाई) उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

(4) मिचिव (मिचाई) पाण्डिचेरी प्रशासन, पाण्डिचेरी।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

8. नागर्का का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फसल/फर्मेशन/ग्रामीण विकास में भावित एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि

(1) डा० परमेश्वर राव, बी० सी० ई० चेलामन चिकाई, विष्णविश्वा-पलनम, 531035।

(2) प्रो० परमेश्वर राष्ट्र, प्रो० इमेरिटस आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेरे।

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का प्रतिनिधि

12. कृषि नथा सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि

13. जल भंगालय मंत्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० ए० चौधरी, जीव विज्ञान विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय

35 बालीगंग, मर्कुन्ड, रोड, कलकत्ता-700019

15. डा० टी० शी० एग० राव, प्रशासी निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेरे, 53003--सदस्य सचिव योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:—

(1) मुद्रा, भूतल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, भौतिकों और अन्य मस्वद्व क्षेत्रकों, प्रौद्योगिकीय संभावनाओं और इन क्षेत्रकों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, आमांशिक और आर्थिक पहलओं के बारे में संगम सूचना और आंकड़े प्रकृत तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़े और सूचना की जांच करना और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिये यदि किसी उपर्युक्तीयकारण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) जल और उप अंकों के लिये फसल पद्धति तैयार करनी गिफारिश करना;

(4) फसल भिन्न कृषि वानिकी, पशुपालन और झेंत्र के लिये उपर्युक्त कृषि प्रोमोशनिंग क्रियाकलापों के बारे में विकारिश करना;

(5) मध्यमांशिक (5 वर्ष) और दीर्घांशिक (10 से 15 वर्ष) में झेंत्र के कृषि विकास के लिये उपर्युक्त स्थीर/कार्यक्रम तैयार करना और उसकी गिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिये अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रकों के विकास के लिये अपेक्षित तीनि गम्भीरी उपायों, विशेष रूप से विनीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में विफारिश करना;

(8) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगम अन्य पहलओं पर विचार करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी० ओ० को अतिरिक्त सदस्य के रूप में मह-योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के सम्बन्ध में मदस्यों के यात्रा भौति/इनिक भौतों पर होने वाला ज्यव, गरकारी मदस्यों के सामले में उन विभागों/भौतानयों/राज्य मरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा बहुत किया जायेगा, जिनसे वे गम्भीर हों, और योजना दल के गैर-मरकारी मदस्यों, के सामले में योजना आयोग द्वारा बहुत किया जायेगा।

7. योजना दल के गम्भीर में गारा पश्चाचार सलाहकार (कृषि), योजना आयोग से किया जाये, जो इस परियोजना की केंद्रीय मिशन के सदस्य सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत कर सकता है, और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करनगा।

आदेश

अदिगा विद्यालय है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत मरकार तथा राज्य मरकारों के गम्भीर भवित्वित मंत्रालयों और विभागों को एक प्रति भेजी जाये।

प्रदृश आदेश विद्यालय जाना है कि संघर्ष को मामांश गूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं० एम० 13043/12/87-एग्री (xii):—कृषि मंत्रालय के कार्यालय की गमीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने सुनावि किया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यकारी कोषक्ष-मापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। भवित्वों की मिशन की 26 मई, 1987 को हुई बैठक बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस कार्य पर और अपे विचार-विमर्श किया गया। यह लियाये किया गया कि देश के 15 कृषिक-जनवायु क्षेत्र कृषि गम्भीरी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के प्राधार पर, कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के पादस्थ (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निपटानी करेंगे और उनके सिरदिशा निर्देश देंगी।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य आतों के साथ-साथ, रत्नकर कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए धैर्यीय योजना दस्तों के गठन का निर्णय लेया गया था। पश्चिमी तटीय भैदान तथा घाट क्षेत्र सम्बन्धी योजना वला भा गठन इस प्रकार होगा:—

क्षेत्र 12 पश्चिम तटीय भैदान तथा घाट क्षेत्र आयोजन वल के सदस्य

1. डा० एम० श्री० काइरेकर,

अध्यक्ष

कुलपति,
कोकण कृषि विश्वविद्यालय,
दापांडी-415712।

सदस्य

2. इस क्षेत्र के अन्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति

- (1) कुलपति केरल कृषि विश्वविद्यालय,
वैलनीकुप्पा, त्रिचुर।
- (2) कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्पटूर
- (3) कुलपति, यू० ए० एम०, धार्खाड, कर्नाटक।

3. इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन आशयुत तथा कृषि सचिव

- (1) कृषि उत्पादन आशयुत, केरल, त्रिवेन्द्रम।
- (2) कृषि सचिव, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
- (3) कृषि उत्पादन आशयुत, कर्नाटक, बंगलौर।
- (4) सचिव (कृषि) गोवा सरकार, पांजी।

4. इस क्षेत्र में सचिव (पशुपालन)

- (1) सचिव, (पशु पालन) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
- (2) सचिव, (पशु पालन), कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
- (3) सचिव, (पशु पालन) महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
- (4) सचिव, (पशु पालन) गोवा सरकार, पांजी।

5. इस क्षेत्र में मुख्य बन संरक्षक

- (1) मुख्य बन संरक्षक, केरल, त्रिवेन्द्रम।
- (2) मुख्य बन संरक्षक, कर्नाटक, बंगलौर।
- (3) मुख्य बन संरक्षक, महाराष्ट्र, पुणे।
- (4) मुख्य बन संरक्षक, गोवा, पांजी।

6. इस क्षेत्र में सचिव (भिजाई)

- (1) सचिव, (भिजाई) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
- (2) सचिव (भिजाई) कर्नाटक सरकार, बंगलौर।
- (3) सचिव (भिजाई) महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।
- (4) सचिव (भिजाई) गोवा सरकार, पांजी।

7. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

8. नावांड का प्रतिनिधि

9. इस क्षेत्र में फमल/फलरोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित एन० जी० औ० का प्रतिनिधि

श्री बसन्त गंगाधारे, गोकुल प्रकल्प प्रतिष्ठान, 2150 जूनेकर हाउस राम मन्दिर के पीछे, रत्नगिरि पाकेट डा० बी० छक्काल, के०। म० एम० पी० परिषद भवन, त्रिवेन्द्रम-685937।

10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

11. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का प्रतिनिधि

12. कृषि तथा मन्त्रालय विभाग का प्रतिनिधि

13. जन संसाधन मन्त्रालय का प्रतिनिधि

14. डा० एन० बालाकृष्णन नायर, अध्यक्ष, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित राज्य समिति, योजना तथा प्राथिक कार्य विभाग, संवित्रित, त्रिवेन्द्रम-695001।

15. प्रो० एम० जी० हनुमलन, अध्यक्ष, म० डी० अर० टी० एक्क, मासांजिक तथा अंतिक परिवर्तन संस्थान, अग्रीर-560072
सदस्य सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय में होंगे:—

(1) मूदा, भूतल और भूगत जल, फसल, पश्चिम, पश्चिम, मीन क्षेत्रों और अन्य सम्बन्धीय क्षेत्रों, प्रौद्योगिकीय मंडायनाओं और इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, मासांजिक और आधिक पहनुओं के बारे में मान सूचना और आंकड़े प्रकार तथा संकलित करना;

(2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रचानतात्मक आयोजन प्रयोगजनों के लिये यदि किसी उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैसला करना;

(3) क्षेत्र और उप क्षेत्रों के लिए फसल पश्चिम सैयर करना और उभकी सिफारिश करना,

(4) फसल भिन्न जूप, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उप-युक्त कृषि प्रोमोशन, क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना

(5) मध्यमावधि (5 वर्ष), और दूरावधि (10 से 15 वर्ष) में क्षेत्र के कृषि विकास के लिये उपर्युक्त स्त्रीमें/कार्यक्रम सैयर करना और उनकी सिफारिश करना;

(6) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति मानवर्द्धी उपायों, विशेष स्वरूप से विस्तीर्ण संस्थाओं की भूमिका की जांच करना और उनके बारे में सिफारिशें करना;

(8) अपने बायं और उद्देश्यों के संगत अन्य पहनुओं पर लोकों करना।

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे हो तो अन्य विशेषज्ञों एन० जी० औ० को अनिवार्य मदस्य के रूप में सह-योजित कर भक्ता है।

6. इस दल की बैठक के सम्बन्ध में सदस्यों के बातों भन्ने/इनिक भन्ने पर होने वाला व्यय, गरकारी मदस्यों के सामग्रे में उन विभागों/मंत्रालयों/राज्य मरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जायेगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर सरकारी सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा बहत किया जायेगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में सारा पलाचार मनाहकार (कृषि), गोजना आयोग से किया जाय, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति के मदस्य सचिव है।

8. योजना दल अपनी अन्तिक रिपोर्ट, अथा आवश्यकता प्रस्तुत कर सकता है और अपनी अन्तिक रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत द्वारा तथा राज्य सरकारों के मध्ये संबंधित मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाये।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनाएं भारत के राज्यवर्ष में प्रकाशित कराया जाये।

संकल्प

सं० एम० 13043/12/87-एसी(XII).—कृषि मनाहकार के कार्य-चालन की समीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने मुख्य दिया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्षेत्र सापेक्ष नई दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि वी० समिति की 26 मई, 1947 को शुरू

बैठक में योजना आयोग के उपचारकी अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और भवित्व विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय दिया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र कृषि सम्बन्धी आयोजना का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि-सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के मक्षस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया। संबंधित केन्द्रीय विभागों के समिति इस समिति के मक्षस्य है, जो इस परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और उनके लिए दिशा-दिशें देती।

3. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य वार्ताओं के साथ-साथ, मत्त्येक कृषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा:—

शेत्र 13 गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र योजना दल के मद्दत्य

1. श्री आर० पाठें सारखी,
कुलपति, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
सरदार कृषि नगर, दासी वाढा-बनासांडा- 385506

मद्दत्य

2. सचिव कृषि गुजरात सरकार,
गांधीनगर
3. सचिव, पशुपालन गुजरात सरकार,
गांधीनगर
4. मुख्य बन संगठक गुजरात सरकार
बडोदरा
5. सचिव, भिजाई, गुजरात सरकार,
गांधीनगर
6. इस क्षेत्र में महकारी भूमि खिकाय बैंकों का प्रतिनिधि
7. नवार्ड का प्रतिनिधि
8. इस क्षेत्र में फसल, फलरोपण/प्रार्थी विकास में संबंधित एन० जी० औ० के प्रतिनिधि

(1) डा० विमल शाह, मार्केट गुजरात इंस्टीट्यूट
आफ एरिया न्यानिंग, गांधीनगर राजमार्ग,
ग्रहमदाबाद- 380054

(2) श्री नवल भाई शाह मार्केट अध्यात्मक और
आयोजन ट्रस्ट, प्रमरनाथ मोसाइटी,
नारायणपुर चार रास्ता, ग्रहमदाबाद- 380016

- (3) श्री वी पटेल, सूरेन्द्र फास्टी, भावनगर
9. योजना आयोग का प्रतिनिधि
10. भारतीय कृषि भवनसंघान परिषद् का प्रतिनिधि
11. कृषि और महकारिता विभाग का प्रतिनिधि
12. जल संमाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
13. प्रो० ए० सी० पांडु, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,
राजकोट, गुजरात
14. प्रो० महेश पाठक, माननद निदेशक, प्रो० इकनामिक
रिसर्च सेटर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
वल्लभ विद्यालय- 388120 (गुजरात)

मद्दत्य-सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे:—

(1) मृदा, भूलूल और भूगत जल, फसल, पश्चाति, पशुओं, मीनक्षेत्रों
और अन्य सम्बद्ध बैंकों प्रौद्योगिकीय सम्भावनाओं और इन
क्षेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, ग्रामाञ्जक और ग्राहिक

पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र तथा
संकलित करना;

- (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना
और प्रचालनामूलक आयोजन प्रयोजनों के लिए, यदि किसी
उप-क्षेत्रीयकरण की आवश्यकता हो, तो उसका फैला करना;
- (3) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पश्चाति नैयार करना और
उसकी सिफारिश करना;
- (4) फसल-भिन्न कृषि विकास और क्षेत्र के लिए उप-
युक्त छापि-प्रोमोशन क्रियालयों के बारे में सिफारिशें करना;
- (5) सध्यमार्गि (5 वर्ष) और दीवार्चिति (10 ते 15 वर्ष) में क्षेत्र
के कृषि-विकास के लिए उपर्युक्त स्कीम्स/कार्यक्रम तैयार कर
और उनसे सिफारिशें करना;
- (6) अपने उद्देश्यों के लिए प्रभेक्षित अध्ययन कार्य शाखा में लेना
और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;
- (7) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति संबंधी उपायों
विशेष रूप से विसीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करना
और उनके बारे में सिफारिशें करना;
- (8) अपने कार्य और उद्देश्यों में संगत अन्य पहलुओं पर विचार
करना;

5. योजना दल का अध्यक्ष, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एम० जी०
ओ० को अतिरिक्त मद्दत्य के रूप में महे० योजित कर सकता है।

6. इस दल की बैठकों के संबंध में मद्दत्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते
पर होने वाला व्यय, सरकारी मद्दत्यों के मामले में उन विभागों/मंत्रालयों/
राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा बहुत किया जाएगा, जिनमें वे सम्बद्ध
होंगे और योजना दल के गैर-सरकारी मद्दत्यों, के मामले में योजना आयोग
द्वारा बहुत किया जाएगा।

7. योजना दल के सम्बन्ध में मारा पकाचार गलाहकार (कृषि)
योजना आयोग से किया जाए, जो इस परियोजना की केन्द्रीय समिति
के गवर्स्य-मत्त्यित है।

8. योजना दल प्रपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत
कर सकता है और प्रपनी अन्तिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत
करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और मद्दत्यों
सार्वत एकता तथा राज्य मंत्रालयों के सभी संबंधित मंत्रालयों और
विभागों को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को गामान्य सूचनार्थ भारत के
राजनीति में प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं० एम०-13043/12/87-एग्री(xii)—कृषि मंत्रालय के कार्य-
वालत की समीक्षा करने हुए प्रधान मंत्री ने मुखाव दिया था कि कृषि
और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को जेल-मापेश नई दिशा दिए जाने
की आवश्यकता है तथा विविधों की समिति की 26 मई, 1987 को हुई बैठक
में योजना आयोग के उपचारकी अध्यक्षता में 20 जुलाई, 1987 को हुई
बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-विमर्श
किया गया यह निर्णय किया गया कि देश के 15 कृषिक-जलवायु क्षेत्र
कृषि सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

2. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कृषिक जलवायु क्षेत्रों के
आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के
सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया।
संचित विभागों के संचित विभागों के मत्त्यित के मद्दत्य के गवर्स्य-
विमर्श की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी करेंगे और उनके लिए
दिशा-निर्देश देंगे।

३. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक कुषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का निर्णय लिया गया था। परिचयों शुल्क क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस प्रकार होगा :—

क्षेत्र १४ परिचयीय शुल्क क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य

१. डा० क० एन० ना० अध्यक्ष
कुलपति, राजस्थान कुषिक विश्वविद्यालय,
बीकानेर-३३४००१ सदस्य
२. सचिव, कुषिक सहकारिता,
राजस्थान, जयपुर
३. सचिव, पशुपालन,
राजस्थान, जयपुर
४. मुख्य बन संरक्षक, राजस्थान,
जयपुर
५. सचिव, सिंचाई,
राजस्थान सरकार, जयपुर
६. इस क्षेत्र में सहकारी भूमि विकास
बैंकों का प्रतिनिधि।
७. नाबांड का प्रतिनिधि
८. इस क्षेत्र में कफल, फल रोपण/ग्रामीण विकास से संबंधित
एन० जी० ओ० का प्रतिनिधि
 - (१) श्री संजीत (बुनकर) राय, एस० डॉल्यू० आर० सी०,
पी० डॉ० तिलोनिया-३०५८१६, जिला प्रभागर, राजस्थान
९. योजना आयोग का प्रतिनिधि
१०. भारतीय कुषिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि
११. कुषिक और सहकारिता विभाग का प्रतिनिधि
१२. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
१३. डा० ईरविं ग्रकाश, निदेशक, केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र
अनुसंधान संस्थान (सी० ए० जैद० आ० आ००)
१४. प्रो० महेश पाठक, मानदि निदेशक,
कुषिक अधिकारीक अनुसंधान केन्द्र सरकार पटेल
विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर-३८५१२० सदस्य—सचिव

४. योजना दल के विचारणीय निषय ये होंगे :—

- (१) मृदा, भूलल और भूगत जल, फसल, पद्धति, पशुओं, मीनखेत्रों
और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों, प्रोटोगिकोथ, संभावनाओं और
इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में पश्चिमीय, लामाजिह और
आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आंकड़े एकत्र
तथा संकलित करना;
- (२) उपर्युक्त (१) में वर्णित आंकड़ों और सूचना की जांच करना
और प्रचालनात्मक आयोजन प्रयोजनों के लिए यदि किसी
उप-क्षेत्रीय करण की आवश्यकता हो, तो उसके फैलाव करना;
- (३) क्षेत्र और उप-क्षेत्रों के लिए फसल-पद्धति तैयार करना और
उसकी सिफारिश करना;
- (४) फसल-भिन्न कुषिक, वानिकी, पशुपालन और क्षेत्र के लिए उप-
युक्त कुषिक-प्रोसेसिंग कियाकलापों के बारे में सिफारिशें
करना;
- (५) मध्यमाधि (५ वर्ष) और दीर्घावधि (१० से १५ वर्ष) में क्षेत्र
के कुषिक-विकास के लिए उपयुक्त स्कीम/हर्फ्ट कम तैयार करना
और उनकी विकारिश करना;

(६) अपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अध्ययन कार्य हाथ में लेन
और यदि आवश्यक हो तो अध्ययन करना;

(७) इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित नीति सम्बन्धी
उपायों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की
जांच करना और उनके बारे में विकारिश करना;

(८) अपने कार्य और उद्देश्यों से संगत अन्य पहलुओं पर विचार
करना;

५. योजना दल का अध्यक्ष यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/एन० जी०
ओ० को भूमिका लेने के लिए अध्यक्ष कर सकता है।

६. इस दल की बैठकों के संवंध में सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक
भत्ते पर होने वाला व्यय, सरकारी सदस्यों के नामले में उन विभागों/
मंत्रालयों/राज्य सरकारी/विश्वविद्यालयों द्वारा बहन किया जाएगा, जिनसे
वे सम्बद्ध हों और योजना दल के गैर-सरकारी सदस्यों के नामले में योजना
आयोग द्वारा बहन किया जाएगा।

७. योजना दल के सम्बन्ध में सारा प्रशासन लालहाल (कुषिक)
योजना आयोग से किया जाए जो इस परियोजना को केन्द्रीय समिति के
सदस्य-समिति है।

८. योजना दल अपनी अन्तरिम रिपोर्ट, यथा-आवश्यकता प्रस्तुत कर
सकता है और अपनी अन्तिम रिपोर्ट ३१ अक्टूबर, १९८९ तक प्रस्तुत
करे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष और सदस्यों भारत
सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों
को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थी भारत
के राजपत्र प्रकाशित कराया जाए।

संकल्प

सं एम०-१३०४३/१२/८७-एग्री(XV)—कुषिक मंत्रालय के कार्य-
चालन की समीक्षा करते हुए प्रधान मंत्री ने सुनाव दिया था कि कुषिक
और ग्रामीण विकास के कार्यकर्ताओं को क्षेत्र-सामेक नई दिशा दिए जाने
की आवश्यकता है। सचिवों की समिति की २६ मई, १९८७ को हुई बैठक
में योजना आयोग के उपायकरण की अध्यक्षता में २० जुलाई, १९८७ को
हुई बैठक में योजना आयोग द्वारा इस विषय पर और आगे विचार-
विमर्श किया गया। यह निर्णय किया गया कि देश के १५ कुषिक-जलवायु
क्षेत्र कुषिक सम्बन्धी आयोजन का आधार होने चाहिए।

२. इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, कुषिक जलवायु क्षेत्रों के
आधार पर कुषिक सम्बन्धी आयोजन करने के लिए योजना आयोग के
सदस्य (कुषिक) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया।
संबंधित केन्द्रीय विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हैं, जो इस
परियोजना की विभिन्न गतिविधियों की नियांरानी करेंगी और उनके लिए
दिशा-निर्देश देंगी।

३. केन्द्रीय समिति की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ
प्रत्येक कुषिक जलवायु क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना दलों के गठन का
निर्णय लिया गया था द्वीप समूह क्षेत्र सम्बन्धी योजना दल का गठन इस
प्रकार होगा :—

क्षेत्र नं १५ द्वीपसमूह क्षेत्र आयोजन दल के सदस्य

१. डा० आ० आ०० पी० अब्रोल, प्रधान निदेशक,
भारतीय कुषिक अनुसंधान परिषद्,
कुषिक भवन, नई दिल्ली-११० ००१ सदस्य
२. (१) सचिव, कुषिक
अंडमान-चूव निकोबार द्वीपसमूह,
पोर्टलैंडर

(2) प्रशासक/निदेशक छवि
लक्षणीय, कवरेसी

3. इस खेत्र में सचिव, पशुपालन

- (1) सचिव, पशुपालन
अंडमान निकोबार द्वीपगम्भू
पोर्टब्लेयर
- (2) प्रशासक/निदेशक,
पशुपालन भवस्य पालन,
लक्षणीय, कवरेसी

4. इस खेत्र के मुख्य बन संरक्षक

- (1) मुख्य बन संरक्षक,
अंडमान निकोबार द्वीपगम्भू प्रशासन,
पोर्टब्लेयर
- (2) बन नियंत्रण और संरक्षक
लक्षणीय कवरेसी

5. इस खेत्र में राज्य सिचाई सचिव

- (1) सचिव, सिचाई
अंडमान निकोबार प्रशासन
- (2) प्रशासक
लक्षणीय कवरेसी

6. इस खेत्र संघ में
गहकारी भूमि विकास बैंकों का प्रतिनिधि

7. नाबांड का प्रतिनिधि

8. योजना प्रायोग का प्रतिनिधि

9. भारतीय कृषि प्रनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि

10. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि

11. डा. सर्वीश बन्द्रन नैयर,
कान्टि बेलट्रेन गार्डन
बिल्डिंग, केरल

12. डा. सी. अर्प्पथराज
उप निदेशक,
एसो इकोनोमिक
रिसर्च सेंटर,
भारत विविधालय,
बिपाक लिंगालीकॉम,
भद्राम-6000 005

मवस्य-सचिव

4. योजना दल के विचारणीय विषय ये होंगे :—

- (1) भूदा, भूतल और भूगत जल कफल, पद्धति, पशुओं मीलों की प्रीर अन्य सम्बद्ध व्यवस्थाओं, प्रौद्योगिकीय गम्भावनाओं और इन खेत्रों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के बारे में संगत सूचना और आकड़े प्रक्रिय तथा संकलित करना;
- (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित आकड़ों और सूचना की जांच करना और प्रवानवाक व्यावरों के लिए नियम विवरण उप-संस्कैलरण की आवश्यकता हो, तो उनका फैला रखना;
- (3) खेत्र और उप-खेत्रों के लिए कफल पद्धति नैयर/ केरल और उसकी सिफारिश करना;
- (4) कफल-मित्र छवि, वानिकी, पशुपालन और खेत्र के लिए उपयुक्त छवि प्रसेटिंग क्रियाकलापों के बारे में सिफारिशें करना;
- (5) मध्यमावधि (5 वर्ष) और दीवावधि (10 से 15 वर्ष) में खेत्र के छवि-विकास के लिए उपयुक्त स्थीमेंकार्यक्रम बैयार करना और उनकी विकारिश करना;
- (6) प्रपने उद्देश्यों के लिए अपेक्षित अव्ययन कार्य हाथ में लेना और यदि प्रवानवक हो तो अव्ययन करना;

(7) इस खेत्रों के विकास के लिए अपेक्षित लीनि सम्बन्धीय उद्देश्यों क्रियेर ला में नियम अंगठियों का भूमिका की जांच करना और उनके बारे में विकारिश करना;

(8) प्रान कार्य प्रयोग उद्देश्यों से संगत प्रब्लेम्स पर विचार करना

5. योजना दल का प्रधन, यदि चाहे तो अन्य विशेषज्ञों/दत्तों जी० औ० को अनियक्त सदस्य के रूप में भृद-योजित हर सहाया है।

6. इस दल की बैठकों के पश्चात में वस्त्रों के वास्त्रा सत्त्व/वित्त भवने पर दौरे बाला अव, नावाहार 10 वर्षों ते उसने में उन विषयों/संबंधियों/राज्य तरहारों/विश्वविद्यालयों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनसे वे सम्बद्ध हों और योग्यता रखने के गैर-मत्तकारों विद्वाँ के मामते में योजना आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

7. योजना दल ने सम्बन्ध में गैर-प्रानार नावाहार (छवि) योजना आयोग से किया जाए, जो इन परियोजना को केन्द्रीय समिति के सदस्य-सचिव है।

8. योजना दल अपनी विनाशक रिपोर्ट मत्ता-आवश्यकता प्रस्तुत कर देगा है और प्रानी अविनम रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 1989 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है हि आयोजन खेत्र के अध्यक्ष और सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य मरकारों के सभा सर्वोच्च संसाधनों और विभागों की संकलन की एक प्रति भेजी जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि नंकल को नामान्य सूचनाएँ भारत ने राजस्व में विकासित गार्डा जाए।

दिनांक, 7 जुलाई, 1988

नंकल

सं. पुम०-13043/12/87-छवि—वह नियम दिया गया है कि नंकल (पत्ता संसाधन), सचिव (ग्रन्तिकर्ता) और सचिव (प्रामीण विकास) भी योजना प्रायोग के गम्भीरकरण संकलन वित्तांक 27 नवम्बर, 1987 के द्वारा छवि-जारायु अंद्रप्राचीन भृदी पर विवादित करने के लिए गठित केन्द्रीय समिति के सदस्य होंगे।

उपरोक्त सदस्यों यदि नियम दिया गया प्रब्र इस प्रकार सूची :—

1. सबस्य (छवि), योजना आयोग	अध्यक्ष
2. नाबांड (छवि एवं महकारिता)	सदस्य
3. सचिव (पर्यावरण और बन)	सदस्य
4. नाबांड (छवि प्रनुसारण और गिरा)	सदस्य
5. नाबांड (योजना)	सदस्य
6. नाबांड (व्य)	सदस्य
7. सचिव (जल संसाधन)	सदस्य
8. सचिव (ग्रन्तिकर्ता)	सदस्य
9. सचिव (प्रामीण विकास)	सदस्य
10. गवाहकार (छवि) योजना प्रायोग	संचालक

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस नंकल का एक प्रति केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष वसी सदस्यों भारत ने भा विभागों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस नंकल को मानान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई विल्सी, दिनांक 1 अगस्त 1988

में एक 1-6/88टी०-13-प्रश्नातिक अहंता मूल्यांकन बोर्ड के प्रधाक्ष के प्रश्नोदत पर भारत सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान सलैम/शागणसी/गोहाटी डारा प्रदान किया गया हस्तशिल्प में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाद्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त थेट्रे में प्रधीनस्थ पद्धों तथा सेक्यारेटों में रोजगार के लिए तस्काल में मान्यता प्रदान करती है।

मुन्द्र सिंह, उप शिक्षा मंत्रालय (टी)

मंत्रालय मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई विल्सी-110001, दिनांक 11 अगस्त 1988

में 23-6/87-एल आई०-राष्ट्रपति एवं द्वारा देखे हैं कि 1 जून 1988 में डाक जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा में संबंधित नियमों में घारे निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे प्रथमतः—

उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियम 43 के अन्त में दिनांक 1-11-87 से संशोधित 5000/- रुपये के बीमे के लिए मासिक प्रीमियम महिल बन्दोबस्ती बीमे में संबंधित मौजूदा सारणी-II के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी-II

डाकघर बीमा निधि—1 जून, 1988 से नामून प्रीमियम

बन्दोबस्ती बीमा

5,000/- रु के बीमे के लिए मासिक प्रीमियम

पालिसी लेते व्यापु जिस पर पालिसी परिपक्व होती है।

समय प्रायः

	35 वर्ष	40 वर्ष	45 वर्ष	50 वर्ष	55 वर्ष	58 वर्ष
(रु)	(रु)	(रु)	(रु)	(रु)	(रु)	(रु)
1	2	3	4	5	6	7

19	26	19	15	12	10	9
20	27	20	16	13	10	10
21	29	21	16	13	11	10
22	32	22	17	14	11	10
23	35	24	18	14	12	10
24	38	26	19	15	12	11
25	42	27	20	16	13	11
26	47	29	21	16	13	12
27	53	32	22	17	14	12
28	61	35	24	18	14	13
29	72	38	26	19	15	13
30	86	42	28	20	16	14
31	..	47	30	21	17	15
32	..	53	32	23	17	15
33	..	61	35	24	18	16
34	..	72	38	26	19	17
35	..	86	42	28	20	18
36	47	30	22	19
37	53	32	23	20

1	2	3	4	5	6	7
38	61	35	25	21
39	72	39	26	22
40	87	43	28	23
41	48	30	25
42	54	33	27
43	62	36	29
44	72	39	31
45	87	43	33
46	48	36
47	55	40
48	63	44
49	73	49
50	88	55

टिप्पणी—1. उपर्युक्त गारिणी के प्रयोजन के लिए “पालिसी लेते समय की आयु” से प्रभित्य उस आयु से है जो प्रथम प्रीमियम के मुताबिक बीमा की तारीख के बाद प्रगति जन्म वितार है।

2. 20,000/- रु और उसमें प्रधिक रु की पालिसी के लिए प्रत्येक बीमा हजार की बीमाकृत राशि के लिए 1/- रु प्रति मास की छठ स्वीकार्य है।

3. गारिणी के प्रयोजन के लिए “पालिसी लेते समय व्यूनतम आयु” 19 वर्ष होती और प्रधिकतम 50 वर्ष होती।

4. व्यूनतम बीमाकृत राशि 10,000/- रु होती किन्तु सभी श्रेणियों में किए गए बीमों की राशि का कुल योग एक लाख रुपए से प्रधिक नहीं होगा।

5. पालिसी 5,000/- रु के यूनिट में ली जा सकती है लेकिन बीमाकृत राशि 10,000/- रु से कम नहीं होती।

(श्रीमती) ज्योत्सना धीमा,
निदेशक (पी० एल० आई०)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई विल्सी, दिनांक 10 अगस्त, 1988

संकल्प

में हिंदी/समिति/88/38/5—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 16-1-87 तथा समर-समष्टि पर मंसोधित मंकल्प संझा हिंदी/समिति/86/38/6 के प्रधीन रेलवे हिंदी याताहार मिति के गठन के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि इस मंकल्प में उल्लिखित जड़ा-जड़ा ‘पीर-सरकारी मदस्य’ गद्द का प्रयोग किया गया है वह वहाँ उत्तर स्थान पर केवल ‘मदस्य’ पढ़ा जाये तथा भवित्व में ‘पीर-सरकारी वद्दीयों’ को केवल ‘मदस्य’ कह कर सम्बोधित किया जाये।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कायालिय, मंत्रिमंडल मंचिवालय, मंसोधीय कार्य विभाग, सोकू सभा तथा राज्य सभा मंचिवालय और भारत सरकार के मध्ये मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि गर्भमाणारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सतीश मोहन वैश, मंचिव, रेलवे बोर्ड

PLANNING COMMISSION

New Delhi-1, the June 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12(7)87-Agri.—Subsequent to Dr. N. Patnaik taking over charge from Shri K. Ramamurthy, as Vice Chancellor, Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar, Shri Patnaik will be the Chairman of the Planning Team for Zone No. 7: Eastern Plateau and Hill Regions constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June, 1988, with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12(10)87-Agri.—Subsequent to Dr. Ramakrishna taking over charge from Dr. S. V. Patil as Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore, Dr. Ramakrishna will be the Chairman of the Planning Team for Zone No. 10: Southern Plateau and Hills Region constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri. dated 3rd June 1988 with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 3rd June 1988

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(I).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, *inter alia*, a decision was taken to set up Zone Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Western Himalayan Region is as follows :—

ZONE NO. 1 : Western Himalayan Region

Members of the Planning Team

Chairmen

1. Dr. Mahatim Singh, Vice Chancellor of the University of Agriculture & Technology, Pant Nagar, Uttar Pradesh.

2. Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone :

Members

(i) Vice Chancellor, Himachal Pradesh Krishi Vishwavidyalaya, Palampur-176002, Himachal Pradesh.

(ii) Vice Chancellor, Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan-173230, Himachal Pradesh.

(iii) Vice Chancellor, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Srinagar.

3. SPCs and Agriculture Secretaries in the Zone :
Members

(i) Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001, Uttar Pradesh.

(ii) Agriculture Production Commissioner, Jammu and Kashmir, Srinagar-190 001, J&K.

(iii) Additional Chief Secretary, Department of Agriculture, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone :
Members

(i) Secretary, Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.

(ii) Secretary, Animal Husbandry, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Secretary, Animal Husbandry, Jammu & Kashmir, Srinagar-190001.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone :
Members

(i) Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001.

(ii) Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Chief Conservator of Forests, J&K, Srinagar-190 001.

6. Secretaries, Irrigation in the Zone :
Members

(i) Secretary, Irrigation, Uttar Pradesh, Lucknow-226 001.

(ii) Secretary, Irrigation, Himachal Pradesh, Simla-171 001.

(iii) Secretary, Irrigation, Jammu & Kashmir, Srinagar-190 001.

7. Representative of Land Development Banks of the Region.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region :
Members

Shri Sugash Mandhapurker, Sutra, P.O. Jagajit Nagar, Solan-173 203, H. P.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Deptt. of Agri. & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Prof. A. S. Purohit, Srinagar University, Srinagar.

Member-Secretary

15. Dr. R. Swarup, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, Himachal Pradesh, University, Shimla, HP.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :—

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(II).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programme of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, *inter-alia*, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Eastern Himalayan Region is as follows :

ZONE NO. 2 : Eastern Himalayan Region

Members of the Planning Team

Chairmen

1. Dr. P. C. Bora, Vice Chancellor, Assam Agriculture University PO Barbhota, Jorhat-785-015, Assam.

2. Vice Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone :

Member

Vice Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, PO Mohanpur, Haringhata, Nadia 741 252, West Bengal.

3. SPCs and Agriculture Secretaries of the States of the Zone :

Members

- (i) Agriculture Production Commissioner, Assam, Dispur.
- (ii) Secretary (Agriculture), West Bengal, Calcutta.
- (iii) Development Commissioner/Secretary, Agriculture Arunachal Pradesh, Itanagar.
- (iv) Development Commissioner/Secretary, Agriculture Manipur, Imphal.
- (v) Agriculture Production Commissioner, Meghalaya, Shillong.
- (vi) Development Commissioner/Secretary, Agriculture, Mizoram, Aizawl.
- (vii) Development Commissioner/Secretary, Agriculture, Nagaland, Kohima.
- (viii) Commissioner-cum-Secretary, Agriculture, Tripura, Agartala.
- (ix) Secretary, Agriculture, Sikkim, Gangtok.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone :

Members

- (i) Secretary, Animal Husbandry, Assam, Dispur.
- (ii) Secretary, Animal Husbandry, West Bengal, Calcutta.
- (iii) Secretary, Animal Husbandry, Arunachal Pradesh, Itanagar.
- (iv) Secretary, Irrigation, Manipur, Imphal.
- (v) Secretary, Animal Husbandry, Manipur, Imphal.
- (vi) Secretary, Animal Husbandry, Mizoram, Aizawl.
- (vii) Secretary, Animal Husbandry, Nagaland, Kohima.
- (viii) Secretary, Animal Husbandry, Tripura, Agartala.
- (ix) Secretary, Animal Husbandry, Sikkim, Gangtok.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone :

Members

- (i) Chief Conservator of Forests, Assam, Guwahati.
- (ii) Chief Conservator of Forests, West Bengal, Calcutta.
- (iii) Chief Conservator of Forests, Arunachal Pradesh, Itanagar.
- (iv) Chief Conservator of Forests, Manipur, Imphal.
- (v) Chief Conservator of Forests, Meghalaya, Shillong.
- (vi) Chief Conservator of Forests, Mizoram, Aizawl.
- (vii) Chief Conservator of Forests, Nagaland, Kohima.
- (viii) Chief Conservator of Forests, Tripura, Agartala.
- (ix) Chief Conservator of Forests, Sikkim, Gangtok.

6. Secretaries of Irrigation in the Zone :

(i) Secretary, Irrigation, Assam, Dispur.

(ii) Secretary, Irrigation, West Bengal, Calcutta.

(iii) Secretary, Irrigation, Arunachal Pradesh, Itanagar.

(iv) Secretary, Irrigation, Manipur, Imphal.

(v) Secretary, Irrigation, Meghalaya, Shillong.

(vi) Secretary, Irrigation, Mizoram, Aizawl.

(vii) Secretary, Irrigation, Nagaland, Kohima.

(viii) Secretary, Irrigation, Tripura, Agartala.

(ix) Secretary, Irrigation, Sikkim, Gangtok.

7. Representative of Cooperative Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region ;

MEMBERS

Shri Natwar Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram P.O. Chuchuyinlang Distt. Mokokchung, Nagaland.

10. Representative of the Planning Commission.
11. Representative of the ICAR.
12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.
13. Representative of the Ministry of Water Resources.
14. Shri V. Rishi, Director, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling, W.B.

MEMBER-SECRETARY

15. Dr. P. D. Saikia, Director, Agro-Economic Research Centre, Assam Agriculture University, P.O. Barbhete, Jorhat-785 015, Assam.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(III).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship

of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the central Committee, *inter-alia*, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Lower Gangetic Plains Region is as follows :

Zone No. 3 : Lower Gangetic Plains Region***Members of the Planning Team***

1. Prof. D. K. Das Gupta, Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Haringhata (West Bengal).

MEMBERS

2. *APCs & Agri. Secretaries in the Zone* Agriculture Production Commissioner, Govt. of West Bengal, Calcutta.

3. *Secretary Animal Husbandry in the Zone* Secretary Animal Husbandry, Govt. of West Bengal, Calcutta.

4. *Chief Conservators of Forests in the Zone* Chief Conservator of Forests, Govt. of West Bengal, Calcutta.

5. *Secretary Irrigation in the Zone* Secretary Irrigation, Govt. of West Bengal, Calcutta.

6. Representative of the Coop. Land Development Bank in the Zone.

7. Representative of NABARD.

8. Specialist/representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region. Shri V. S. Agarwal, Chairman, Rural Development Standing Committee, Bharat Chamber of Commerce, Bharat Chambers, 28, Hemant Basu Sarani, Calcutta-I.

9. Representative of the Planning Commission.

10. Representative of the ICAR.

11. Representative of the Department of Agriculture & Coop.

12. Representative of the Ministry of Water Resources.

13. Prof. A. K. Saha, Presidency College, Calcutta.

Director of Agro-Economic Research Centre in the Zone***Member-Secretary***

14. Prof. S. N. Datta, Director of Agro-Economic Research Centre, Vishwabharati University, Shantiniketan, West Bengal-751235.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.IV.—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Middle Gangetic Plains Region is as follows :

Zone No. 4 : Middle Gangetic Plains Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. Kirti Singh, Vice-Chancellor, Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Narendra Nagar, Faizabad (U.P.).

MEMBERS

2. Vice-Chancellors of other Agrl. Universities in the Zone

Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural University, Pusa—Samastipur—Bihar—848125.

3. APCs and Agri. Secretaries in the Zone

- (i) Agriculture Production Commissioner, Govt. of U.P., Lucknow.
- (ii) Agriculture Production Commissioner, Govt. of Bihar, Patna.

4. Secretaries Animal Husbandry in the Zone

- (i) Secretary Animal Husbandry, Govt. of U.P., Lucknow.
- (ii) Secretary Animal Husbandry, Govt. of Bihar, Patna.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone

- (i) Chief Conservator of Forests, Govt. of U.P. Lucknow.
- (ii) Chief Conservator of Forests, Govt. of Bihar, Patna.

6. Secretaries Irrigation in the Zone

- (i) Secretary Irrigation, Govt. of U.P. Lucknow.
- (ii) Secretary Irrigation, Govt. of Bihar, Patna.

7. Representative of Coop. Land Development Bank's Federation in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. Specialist/representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region

Shri Prem Bhai, Director, Agrindus Institute, Banwari Sewashram, Govindpur, Mirzapur Distt., U.P.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Coop.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Dr. K. S. Bilgrami, Bhagalpur University, Bhagalpur.

Member-Secretary

15. Prof. S. K. Datta, Director, Agro-Economic Centre, Vishwabharati University, Shantiniketan (West Bengal)—731235.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(V).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Upper Gangetic Plains Region* is as follows:

*Zone No. 5 Upper Gangetic Plains Region
Members of the Planning Team*

CHAIRMAN

1. Shri S. S. Ahmed.

Vice-Chancellor, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur, Uttar Pradesh.

MEMBERS

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

(i) Vice-Chancellor of Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar, Nainital, Uttar Pradesh.

(ii) Vice-Chancellor, Narendra Deva University of Agriculture and Technology, Faizabad, Uttar Pradesh.

3. APCs and Agriculture Secretaries in the State
Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.

4. Secretary, Animal Husbandry in the Zone,
Secretary, Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone,
Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, Lucknow.

6. State Secretary, Irrigation in the Zone,
Secretary, Irrigation, Uttar Pradesh, Lucknow.

7. Representative of Cooperative Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit, plantation rural development in the region
Shri Ramesh Srivastava, Sarvodaya Ashram, Sikandarpur, Distt. Hardoi, Uttar Pradesh.

10. Representative of the Planning Commission

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture and Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Prof. J. S. Singh, Department of Ecology, Banaras Hindu University, Varanasi.

Member-Secretary

15. Prof. A. D. Sharma, Hon. Director, Agri-Economic Research Centre, University of Allahabad, Allahabad-221 002.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the agro-processing activities suitable for the region in the medium (5 years) as well as longterm (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri. (VI).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Trans-Gangetic Plains Region* is as follows :—

Zone No. 6 : Trans-Gangetic Plains Region

Members of the Planning Team

CHAIRMAN

1. Dr. Har Swaroop Singh
Vice-Chancellor, Haryana Agricultural University
Hissar-12004.

MEMBERS

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone
 - (i) Vice Chancellor, Punjab Agricultural University Ludhiana.
 - (ii) Vice-Chancellor, Rajasthan Agricultural University Bikaner.
3. APCs & Agriculture Secretaries in the Zone
 - (i) Development Commissioner, Punjab, Chandigarh.
 - (ii) Secretary, Agriculture, Haryana, Chandigarh.
 - (iii) Secretary, Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
 - (iv) Secretary, Agriculture, Delhi Administration, Delhi.
4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone
 - (i) Secretary, Animal Husbandry, Punjab, Chandigarh.
 - (ii) Secretary, Animal Husbandry, Haryana, Chandigarh.
 - (iii) Secretary, Animal Husbandry, Rajasthan, Jaipur.
 - (iv) Secretary, Animal Husbandry, Delhi.
5. Chief Conservators of Forests in the Zone
 - (i) Chief Conservator of Forests, Punjab, Chandigarh.
 - (ii) Chief Conservator of Forests, Haryana, Chandigarh.
 - (iii) Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.
 - (iv) Chief Conservator of Forests & Wildlife, Delhi.
6. State Secretaries, Irrigation in the Zone
 - (i) Secretary, Irrigation, Government of Punjab, Chandigarh.
 - (ii) Secretary, Irrigation, Government of Haryana, Chandigarh.
 - (iii) Secretary, Irrigation, Government of Rajasthan, Jaipur.
 - (iv) Secretary, Irrigation & Flood Control, Delhi.
7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone
8. Representative of NABARD.
9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit, plantation/rural development in the region.
 - (i) Sunder Lal, RSWRC, Post Office, Khari-123101.
 - (ii) Rewari, Tehsil, Distt. Mohindergarh, Haryana.
10. Representative of the Planning Commission.
11. Representative of the Indian Council of Agricultural Research.
12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.
13. Representative of the Ministry of Water Resources.
14. Prof. H. Y. Mohan Ram, Department of Botany, Delhi University, Delhi.

MEMBER-SECRETARY

15. Dr. J. P. Singh, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, Delhi University, Delhi-110007.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri. (VII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the Concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for

each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Eastern Plateau and Hills Region is as follows :

Zone No. 7 : Eastern Plateau and Hill Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Shri K. Ramamurthy,
Vice-Chancellor, Orissa University of
Agriculture and Technology,
Bhubaneshwar.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

- (i) Vice-Chancellor, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya Mohanpur—Nadia.
- (ii) Vice-Chancellor, Birsa Agricultural University—Ranchi.
- (iii) Vice-Chancellor, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya—Raipur, M.P.
- (iv) Vice-Chancellor Punjab Rao Krishi Vidyalaya Akola, Maharashtra.

3. APCs & Agriculture Secretaries in the Zone

- (i) Agriculture Production Commissioner, Bihar, Patna.
- (ii) Secretary Agriculture, West Bengal—Calcutta.
- (iii) Commissioner-cum-Secretary Agriculture, Orissa—Bhubaneshwar.
- (iv) Agriculture Production Commissioner, Madhya Pradesh—Bhopal.
- (v) Secretary, Agriculture Maharashtra—Bombay.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone

- (i) Secretary, Animal Husbandry, Bihar—Patna.
- (ii) Secretary, Animal Husbandry, West Bengal—Calcutta.
- (iii) Secretary, Animal Husbandry, Orissa—Bhubaneshwar.
- (iv) Secretary, Animal Husbandry, Madhya Pradesh Bhopal.
- (v) Secretary, Animal Husbandry, Maharashtra—Bombay.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone

- (i) Chief Conservator of Forests Bihar—Patna.
- (ii) Chief Conservator of Forests West Bengal, Calcutta.
- (iii) Chief Conservator of Forests Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh—Bhopal.
- (v) Chief Conservator of Forests—Maharashtra—Pune.

6. State Secretaries, Irrigation in the Zone

- (i) Secretary, Irrigation, Govt. of Bihar—Patna.
- (ii) Secretary, Irrigation, Govt. of West Bengal—Calcutta.
- (iii) Secretary, Irrigation, Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Secretary, Irrigation, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal.
- (v) Secretary, Irrigation, Govt. of Maharashtra, Bombay.

7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone

8. Representative of NABARD.

9. Representatives of NGOs concerned with crop, fruit, plantation/rural development in the region.

1. Representative of Ramakrishna Mission, Ranchi.
2. Achyut Das
S.W.R.C.
P.O. Kashipur,
Koraput—Orissa

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the Indian Council of Agricultural Research.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Dr. R. K. Kutti, Head, Centre for studies in Resources Engineering, IIT, POWAI, Bombay-400076.

Member-Secretary

15. T. V. S. Rao,
Incharge-Director,
Agro-Economic Research Centre,
Andhra University,
Waltair-530003.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned, studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri.(VIII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Central Plateau and Hills Region* is as follows :

Zone No. 8 : Central Plateau and Hills Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. D. K. Sharma
Vice-Chancellor of Jawahar Lal Nehru
Krishi Vishwavidyalaya,
Jabalpur (M.P.)
482004.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.

- (i) Vice-Chancellor,
Chandrashekhar Azad University of Agriculture & Technology,
Kanpur.
- (ii) Vice Chancellor,
Rajasthan,
Agricultural University,
Bikaner.

3. All APCs and Agriculture Secretaries of all the States in the Zone.

- (i) Agriculture Production Commissioner,
Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (ii) Agriculture Production Commissioner,
Uttar Pradesh,
Lucknow.
- (iii) Secretary Agriculture,
Rajasthan,
Jaipur.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.

- (i) Secretary, Animal Husbandry,
Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (ii) Secretary,
Animal Husbandry,
Uttar Pradesh,
Lucknow.
- (iii) Secretary, Animal Husbandry,
Rajasthan,
Jaipur.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone.

- (i) Chief Conservator of Forests,
M. P., Bhopal.
- (ii) Chief Conservator of Forests,
U.P., Lucknow.
- (iii) Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

6. State Secretary, Irrigation in the Zone.

- (i) Secretary Irrigation,
M.P., Bhopal.
- (ii) Secretary Irrigation,
U.P., Lucknow.
- (iii) Secretary Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

7. Representative of Coop. Land Development Banks Federation.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region.

- (i) Shri Bhartandu Prakash Vigyan,
Shiksha Kendra, Tarahi Musli Village,
P.O. Tandwani, Distt. Banda, U.P.

(ii) Dr. D. D. Narula,
53, Jawahar Nagar,
Near Telephone Exchange,
Jaipur-302004
Tel. No. : 64587 (Res.)

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Shri M. V. Buch,
Chairman,
National Centre for Human Settlement and Environment, Bhopal.

15. Dr. M. M. Rai,
Dean, Faculty of Agriculture,
Agri-Economic Research Centre,
J. K. Krishi Vishwavidyalaya,
Jabalpur-482414.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTIONS

No. M-13043/12/87-Agri.(IX).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Western Plateau and Hills Region* is as follows :

Zone No. 9 : Western Plateau and Hills Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. K. R. Pawar
Vice-Chancellor,
Marathwada Krishi Vishwavidyalaya,
Parbhani-431402.
Maharashtra.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.

- (i) Vice-Chancellor, M. P. K. Rabari
Ahmednagar,
Maharashtra.
- (ii) Vice-Chancellor,
Punjabrao Krishi Vidyapeeth,
Akola,
Maharashtra.
- (iii) Vice-Chancellor, J.N.K.V.V.
Jabalpur,
Madhya Pradesh.
- (iv) Vice-Chancellor,
Rajasthan Agricultural University,
Bikaner.

3. APCs and Agriculture Secretaries of the Zone

- (i) Secretary, Agriculture,
Maharashtra,
Bombay.
- (ii) Agriculture Production Commissioner,
Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (iii) Secretary-Agriculture,
Rajasthan,
Jaipur.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.

- (i) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Maharashtra,
Bombay.
- (ii) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (iii) Secretary,
Animal Husbandry,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone.

- (i) Chief Conservator of Forests,
Maharashtra,
Pune.
- (ii) Chief Conservator of Forests,
Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (iii) Chief Conservator of Forests,
Rajasthan,
Jaipur.

6. State Secretaries, Irrigation in the Zone.

- (i) Secretary, Irrigation,
Government of Maharashtra,
Bombay.
- (ii) Secretary, Irrigation,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.
- (iii) Secretary, Irrigation,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

7. Representative of Coop. Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop., fruit plantation/rural development in the region.

- (i) Shri S. P. Salunkhe,
Area Gaurav Pratishtha, P.B. No. 1202,
67, Hadapear Industrial Estate,
Pune (M.S.)-11013.
- (ii) Prof. P. N. Bendakar,
"KUNANBANT"
820/2, Shivaji Nagar,
Pune-411 004.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

*14. Shri D. V. Harnkar,
Director, Social Forestry,
Nagpur.*

Member-Secretary

*15. Dr. V. S. Chitre,
Director,
Agro-Economic Research Centre,
Goghal Institute of Politics & Economics,
Pune-411 004.*

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;

- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri.(X).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Southern Plateau and Hills Region is as follows :

Zone No. 10. Southern Plateau and Hills Region Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. S. V. Patil,
Vice-Chancellor of the University of
Agricultural Sciences,
Bangalore-560024.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.

- (i) Vice-Chancellor,
University of Agricultural Sciences,
Madras.
- (ii) Vice-Chancellor,
Andhra Pradesh Agricultural University,
Rajendra Nagar,
Hyderabad.
- (iii) Vice-Chancellor,
Tamil Nadu Agricultural University,
Coimbatore.

3. All APCs and Agricultural Secretaries of all the States in the Zone.

- (i) Agricultural Production Commissioner,
Karnataka,
Bangalore.
- (ii) Agricultural Production Commissioner,
Andhra Pradesh,
Hyderabad.
- (iii) Commissioner & Secretary Agriculture,
Tamil Nadu,
Madras.

4. Secretaries Animal Husbandry in the Zone.

- (i) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Karnataka,
Bangalore.
- (ii) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad,
- (iii) Secretary, Animal Husbandry,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone

- (i) Chief Conservator of Forests,
Karnataka.
Bangalore.
- (ii) Chief Conservator of Forests,
Andhra Pradesh,
Hyderabad.
- (iii) Chief Conservator of Forests,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

6. State Secretaries, Irrigation in the Zone.

- (i) Secretary, Irrigation,
Government of Karnataka,
Bangalore.
- (ii) Secretary, Irrigation,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.
- (iii) Secretary, Irrigation,
Government of Tamil Nadu,
Madras.

7. Representative of Co-op. Land Development Banks in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop., fruit Plantation/fruit development in the region.

- (i) Mr. Nainder Bedi,
Young India's Project, Penukonda-515170
Anantapur District,
Andhra Pradesh.
- (ii) Prof. R. Radhakrishnan,
Director,
Centre for Economic & Social Studies,
Nizamia Conservatory Campus,
Begumpet,
Hyderabad-500016.

10. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representatives of the Department of Agriculture & Cooperation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.

14. Prof. Madhav Godgil,
Indian Institute of Science,
Bangalore.

Member-Secretary

15. Dr. C. Arputheraj
Deputy Director,
Agro-economic Research Centre,
University of Madras,
Chennai: Triplicane,
Madras-600005.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution so communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri.(XI).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programme of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1980. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *East Coast Plains and Hills* Region is as follows :

Zone No. 11 : East Coast Plains and Hills Region

*Members of the Planning Team**Chairman*

1. Dr. Appa Rao,
Vice-Chancellor,
Andhra Pradesh Agricultural University,
Hyderabad-500030.

Members

2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone

- (i) Vice-Chancellor, Orissa University of Agriculture & Technology, Bhubaneshwar.
- (ii) Vice-Chancellor, Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore.

3. APC's and Agriculture Secretaries in the Zone

- (i) Agriculture Production Commissioner, Andhra Pradesh, Hyderabad
- (ii) Commissioner & Agriculture Secretary, Tamil Nadu, Madras.
- (iii) Agriculture Commissioner-cum-Secretary, Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Secretary (Agriculture), Government of Pondicherry, Pondicherry.

4. Secretaries (Animal Husbandry) in the Zone

- (i) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (ii) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Tamil Nadu, Madras.
- (iii) Secretary (Animal Husbandry), Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Secretary (Animal Husbandry), Pondicherry Administration, Pondicherry.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone

- (i) Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (ii) Chief Conservator of Forests, Tamilnadu, Madras.
- (iii) Chief Conservator of Forests, Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Conservator of Forests/Forest & Wildlife Officer, Pondicherry Administration, Pondicherry.

6. Secretaries (Irrigation) in the Zone

- (i) Secretary (Irrigation), Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
- (ii) Secretary (Irrigation), Government of Tamilnadu, Madras.
- (iii) Secretary (Irrigation), Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
- (iv) Secretary (Irrigation), Pondicherry Administration, Pondicherry.

7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone.

8. Representative of NABARD.

9. Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the Zone

- (i) Dr. Parmeshwar Rao, B.C.T. Yellamanchilli, Vishakhapatnam-531055.

- (ii) Professor Someshwar Rao, Prof. Emeritus, University Waltair.

11. Representative of the Planning Commission.

11. Representative of the ICAR.

12. Representative of the Department of Agriculture & Co-operation.

13. Representative of the Ministry of Water Resources.
 14. Dr. A. Choudhary, Department of Zoology, Calcutta University, 25, Ballygunge Circular Road, Calcutta-700019.

Member-Secretary

15. Dr. T. V. S. Rao, Incharge Director, Agro-Economic Research Centre, Andhra University, Waltair-530003.
 4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, Co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agrl.(XII).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific re-orientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The commission of the Planning Team for the *West Coast Plains and Ghats Region* is as follows :

*Zone No. 12 : Western Plains and Ghat Region**Members of the Planning Team.*
Chairman

1. Dr. S. P. Kadrankar,
Vice-Chancellor,
Konkan Krishi Vishwa Vidyalaya,
Depali-415712

*Members**2. Vice-Chancellors of other Agricultural Universities in the Zone.*

- (i) Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University, Vallanikhar, Trichur.
- (ii) Vice-Chancellor, Tamilnadu Agriculture University, Coimbatore.
- (iii) Vice-Chancellor, U.A.S., Dharwad, Karnataka.

3. All APCs and Agriculture Securities of all the States in the Zone.

- (i) Agriculture Production Commissioner, Kerala, Trivandrum.
- (ii) Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra, Bombay.
- (iii) Agriculture Production Commissioner, Karnataka, Bangalore.
- (iv) Secretary, Agriculture, Government of Goa, Panaji.

4. Secretaries, Animal Husbandry in the Zone.

- (i) Secretary (Animal Husbandry), Government of Kerala, Trivandrum.
- (ii) Secretary (Animal Husbandry), Government of Karnataka, Bangalore.
- (iii) Secretary (Animal Husbandry), Government of Maharashtra, Bombay.
- (iv) Secretary (Animal Husbandry), Government of Goa, Panaji.

5. Chief Conservators of Forests in the Zone.

- (i) Chief Conservator of Forests, Kerala, Trivandrum.
- (ii) Chief Conservator of Forests, Karnataka, Bangalore.
- (iii) Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Pune.
- (iv) Chief Conservator of Forests, Goa, Panaji.

6. Secretaries, Irrigation in the Zone.

- (i) Secretary (Irrigation), Government of Kerala Trivandrum.
- (ii) Secretary (Irrigation), Government of Karnataka, Bangalore.
- (iii) Secretary (Irrigation), Government of Maharashtra, Bombay.
- (iv) Secretary (Irrigation), Government of Goa, Panaji.

*7. Representative of Cooperative Land Development Bank in the Zone.**8. Representative of NABARD.**9. Representatives of NGOs concerned with crop, fruit Plantation/rural development in the Zone.*

- (i) Shri Vasant Gangavara, Gokal Prakalp Pratishthan, 2150, Juvakar House, Behind Ram Mandir, Ratangiri-415612.
- (ii) Dr. B. Ekbal, KASP. Parishad Bhavan, Trivandrum-689937.

*10. Representative of the Planning Commission.**11. Representative of the ICAR.**12. Representative of the Department of Agriculture & Cooperation.**13. Representative of the Ministry of Water Resources.*

14. Dr. N. Balakrishnan Nair, Chairman, State Committee on Science, Technology and Environment, Planning and Economic Affairs Department, Secretariat, Trivandrum-695001.

Member-Secretary

15. Prof. S. G. Hanumantha, Head A.D.R.T. Unit, Institute for Social and Economic Change, Bangalore-560072.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, Co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution of communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri-XIII.—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this

Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, the decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the *Gujarat Plains and Hills Region* are as follows :

Zone 15 : Gujarat Plains and Hill Regions
Members of the Planning Team

Chairman

1. Shri R. Parthasarathy,
Vice Chancellor,
Gujarat Agricultural University,
Sardar Krishi Nagar, Dentiwada,
Banaskantha-385506.

Members

- 2. Secretary, Agriculture,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.
- 3. Secretary, Animal Husbandry,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.
- 4. Chief Conservator, Forests,
Government of Gujarat,
Baroda.
- 5. Secretary, Irrigation,
Government of Gujarat,
Gandhi Nagar.
- 6. Representative of Coop. Land Development Banks in
the Zone.
- 7. Representatives of NABARD.
- 8. Representative of NGOs concerned with crop, fruit
plantation/rural development in the region.
- (i) Dr. Vimal Shah,
C/o Gujarat Institute of area Planning, Gandhi-
nagar Highway, Ahmedabad-580054.
- (ii) Shri Nawalbhai Shah,
C/o Abhyaskum & Aayojan Trust, 2 Amarnath
Society, Narinipura Char Rusta, Ahmedabad-
380016.
- (iii) Shri V. Patel, Sprendra Farms, Bhavnagar.
- 9. Representative of the Planning Commission.
- 10. Representative of the ICAR.
- 11. Representative of the Department of Agriculture and
Co-operation.
- 12. Representative of the Ministry of Water Resources.
- 13. Prof. S. C. Pandeya, Saurashtra University, Rajkot
Gujarat.

Member-Secretary

14. Prof. Mahesh Pathak, Hon. Director, Agro Economic Research Centre, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-868120 (Gujarat).

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri(XIV).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 15 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Western Dry Region is as follows :

Zone No. 14 : Western Dry Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. K. N. Nag,
Vice Chancellor,
Rajasthan Agricultural University,
Bikaner-334001.

Members

2. Secretary,
Agriculture Cooperation,
Rajasthan, Jaipur.
3. Secretary, Animal Husbandry,
Government of Rajasthan,
Jaipur.
4. Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

- 5. Secretary, Irrigation
Government of Rajasthan,
Jaipur.
- 6. Representative of Coop. Land Development Banks in the Zone.
- 7. Representatives of NABARD.
- 8. Representative of NGOs concerned with crop, fruit plantation/rural development in the region.
- (i) Shri Sanjiv (Bunker) Roy, S.W.R.C.,
P.O. Tilonia-305816, Distt. Ajmer, Rajasthan.
- 9. Representative of the Planning Commission.
- 10. Representative of the ICAR.
- 11. Representative of the Department of Agriculture and Co-operation.
- 12. Representative of the Ministry of Water Resources.
- 13. Dr. Ishwar Prakash, Director, Central Arid Zone Research Institute (CAZRI) Jodhpur (Rajasthan) 342005.

Member-Secretary

14. Prof. Mahesh Pathak, Hon. Director, Agro Economic Research Centre, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388380.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to, soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;
- (ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;
- (iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;
- (iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;
- (v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;
- (vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;
- (vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;
- (viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, co-opt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. M-13043/12/87-Agri(XV).—The Prime Minister while reviewing the working of the Ministry of Agriculture suggested that area specific reorientation needs to be given to the programmes of Agriculture and Rural Development. This subject was further discussed in a meeting of the Committee of Secretaries on 26th May, 1987 and by the Planning Commission in a meeting held under the chairmanship of Deputy Chairman on 20th July, 1987. It was decided that 13 Agro-climatic Zones of the country should serve as the basis of agricultural planning.

2. As a result of these deliberations, a Central Committee was set up under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission for organising agricultural planning on the basis of Agro-climatic Regions. The Secretaries of the concerned Central Departments are the members of this Central Committee which would oversee and guide the various activities of the Project.

3. During the first meeting of the Central Committee, inter-alia, a decision was taken to set up Zonal Planning Teams for each Agro-climatic Region. The composition of the Planning Team for the Islands Region is as follows :

Zone No. 15 : The Islands Region

Members of the Planning Team

Chairman

1. Dr. P. P. Abrol,
Deputy Director General,
I.C.A.R., Krishi Bhawan,
New Delhi-110001.

Members

2. Secretary Agriculture

- (i) Secretary Agriculture, Andaman & Nicobar Islands, Portblair.
- (ii) Administrator/Director Agriculture, Lakshadweep, Kavarathi.

3. Secretary Animal Husbandry in the Zone

- (i) Secretary, Animal Husbandry, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.
- (ii) Administrator/Director, Animal Husbandry, Fisheries, Lakshadweep, Kavarathi.

4. Chief Conservators of Forests in the Zone.

- (i) Chief Conservator of Forest, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.
- (ii) Forest & Wild Life Officer, Lakshadweep, Kavarathi.

5. State Secretary, Irrigation in the Zone

- (i) Secretary, Irrigation, Andaman & Nicobar Islands Admn. Portblair.
- (ii) Administrator, Lakshadweep, Kavarathi.

6. Representative of the Coop. Land Development Bank's Federation in the Zone.

7. Representative of the NABARD.

8. Representative of the Planning Commission.

9. Representative of the ICAR.

10. Representative of the Ministry of Water Resources.

11. Dr. Satish Chandran Nair, Santhi Belhaven Garden, Trivandrum, Cochin.

Member-Secretary

12. Dr. C. Arputharaj, Deputy Director, Agro-Economic Research Centre, University of Madras Choolai Trichy, Madras-600 034.

4. The terms of reference of the Planning Team are as follows :

- (i) To collect and collate relevant information and data with respect to soil, surface and underground water, cropping pattern, livestock, fisheries and other relevant sectors, technological possibilities and environmental, social and economic factors with respect to the sectors;

(ii) to examine data collected at (i) and decide on sub-regionalization, if any, required for operational planning purposes;

(iii) to derive and recommend cropping patterns for the region or sub-regions;

(iv) to make recommendations with regard to non-crop agriculture, forestry, animal husbandry and agro-processing activities suitable for the region;

(v) to formulate and recommend suitable schemes/programmes for the agricultural development of the region in the medium (5 years) as well as long-term (10 to 15 years); time phasing of such proposals;

(vi) to undertake and if necessary get Commissioned studies required for its objectives;

(vii) to examine and recommend policy measures required for the development of the sectors and in particular the role of financial institutions in supporting such development;

(viii) to consider any other aspect relevant to its work and objectives.

5. The Chairman, Planning Team may, if he so desires, coopt other experts/NGOs as additional members.

6. The expenditure on TA/DA of the members of the Team in connection with the meetings of the Group will be borne in respect of official members by the Departments/Ministries/State Governments/Universities to which the members belong and by the Planning Commission for the non-official Members of the Planning Team.

7. All correspondence regarding the Planning Team may be addressed to Adviser (Agri.), Planning Commission who is Member-Secretary of the Central Committee of this Project.

8. The Planning Team may submit interim reports as and when required and shall submit its final report by 31st October, 1989.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 7th July 1988

No. M-13043/12/87-Agri.—It has since been decided that Secretary (Water Resources), Secretary (Space) and Secretary (Rural Development) will also be Members of the Central Committee for organising Agriculture Planning on the basis of Agro-Climatic Zones set up vide Planning Commission's Resolution of even number, dated 27th November, 1987. With the addition of the above mentioned members, the composition of the Central Committee would now be as follows :

Chairman

1. Member (Agriculture) Planning Commission.

Members

2. Secretary (Agriculture & Cooperation)

3. Secretary (Environment & Forests)

4. Secretary (Agricultural Research & Education)

5. Secretary (Planning)

6. Secretary (Expenditure)

7. Secretary (Water Resources)

8. Secretary (Space)

9. Secretary (Rural Development)

Convenor

10. Adviser (Agriculture), Planning Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Central Committee and to all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL
Director (Administration)

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)**

New Delhi, the 1st August 1988

No. F. 1-6/88.T.13.—On the approval of the Chairman Board of Assessment for Educational Qualification, the Government of India has been pleased to recognise with immediate effect the three year diploma course in Handloom Technology awarded by the Indian Institute of Handloom Technology at Salem/Varanasi/Gauhati for the purpose of employment to subordinate posts and services under the Central Government in the appropriate field.

SUNDAR SINGH
Dy. Educational Adviser (T)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)**

New Delhi-110 001, the 11th August 1988

No. 23-6/87-LI.—The President hereby directs that with effect from 1st June 1988 the following further amendments shall be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance namely:—

In the said rules, at the end of rule 43, of POIF Rules, the existing table II relating to Endowment Assurances with monthly premium for an assurance of Rs. 5000/- revised with effect from 1-11-87 will be substituted by the following table:—

Table II
Post Office Insurance Fund—Premiums in force from 1st June 1988.

ENDOWMENT ASSURANCES

Monthly premiums for an Assurance of Rs. 5,000/-

Age at entry	Policy maturing at the age				
	35 Yrs. (Rs.)	40 Yrs. (Rs.)	45 Yrs. (Rs.)	50 Yrs. (Rs.)	55 Yrs. (Rs.)
19	26	19	15	12	10
20	27	20	16	13	10
21	29	21	16	13	11
22	32	22	17	14	11
23	35	24	18	14	12
24	38	26	19	15	11
25	42	27	20	16	13
26	47	29	21	16	13
27	53	32	22	17	14
28	61	35	24	18	14
29	72	38	26	19	15
30	86	42	28	20	16
31	—	47	30	21	17
32	—	53	32	23	17
33	—	61	35	24	18
34	—	72	38	26	19
35	—	86	42	28	20
36	—	—	47	30	22
37	—	—	53	32	23
38	—	—	61	35	25
39	—	—	72	39	26
40	—	—	87	43	28
41	—	—	—	48	30
42	—	—	—	54	33
43	—	—	—	62	36
44	—	—	—	72	39
45	—	—	—	87	43
46	—	—	—	—	48
47	—	—	—	—	55
48	—	—	—	—	63
49	—	—	—	—	73
50	—	—	—	—	88

Note :—1. For the purpose of above Table ‘age at entry’ means the age next birthday following the date of payment of the first premium.

2. For a policy of Rs. 20,000/- and above a rebate of Re. 1/- per month per twenty thousand of sum assured is admissible.

3. For the purpose of the table “minimum age at entry” will be 19 years of age and maximum 50 years.

4. The minimum sum assured shall be Rs. 10,000/- but not more than an aggregate of Rs. one lakh in all classes of insurance taken together.

5. The policies can be taken in the units of Rs. 5,000/- but not less than Rs. 10,000/- sum assured.

MRS. JYOTNSA DIESH
Director (PLI)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th August 1988

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/83/38/5.—With reference to the formation of Railway Hindi Salahkar Samiti under the Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution No. Hindi/Samiti/86/38/6 dated 16-1-87 amended from time to time, it has been decided that word 'Member' should only be used wherever the words 'Non-official Member' have been used

in this resolution and in future 'Non-official Members' be addressed as 'Members' only.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secy., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secys. and Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. VAISHI
Secy., Railway Board

